हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 341 बेमेतरा, शुक्रवार 07 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

मुख्यमंत्री ने 'मेरी बेटी-मेरा अभिमान' अभियान का किया शुभारंभ

15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान, हर गांव में मुक्तिधाम और हर बालिका के लिए स्कूलों में बनेगा शौचालय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी 'मेरी बेटी-मेरा अभिमान' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका

शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शौचालय की लागत 4.30 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपए की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे, जिनकी प्रति इकाई लागत 6 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त 18.22 करोड़ रुपए की लागत से 549 मुक्तिधामों का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी प्रति इकाई लागत 3.32 लाख रुपए निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद अथवा डिफंक्ट बोरवेलों में 52.14 करोड़ रुपए की लागत से सैंड फिल्टर एवं रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। प्रति इकाई लागत लगभग 52 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इससे भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत कर शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

ग्रामीण विकास और रोजगार का सबसे बड़ा अभियान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। योजना के अंतर्गत सभी विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति से किया जाएगा तथा मजदूरी की दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत–2047' के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यों के लिए राज्य में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। भारत सरकार से योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का रखा गया विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों का संतुलित ध्यान रखा गया है। कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे खेती और रोजगार दोनों प्रभावित न हों।

318 प्रकार के विकास कार्यों से बदलेगी गांवों की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 318 प्रकार के कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनमें 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण अधोसंरचना विकास कार्य, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य तथा 35 प्रकार के जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भू-जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं ग्रामीण अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, प्रयोगशाला, किचन शेड, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुक्तिधाम और पशु चिकित्सालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

मुख्यमंत्री ने बताया कि आजीविका संवर्धन के अंतर्गत ग्रामीण हाट-बाजार, कृषि उपज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मत्स्य पालन तथा पशुपालन से संबंधित अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

आसाराम को झटका, अंतरिम जमानत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नईदिल्ली, एजेंसी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान पर कि एम्स की रिपोर्ट की सिफारिशों का पूरी तरह और सही भावना के साथ पालन किया जाएगा, बेंच ने आदेश दिया कि आसाराम अपनी पसंद के ट्रेंड केयरटेकर की सेवाएं 24 घंटे ले सकते हैं। बेंच ने कहा हमने एम्स के 31 जुलाई, 2026 के पत्र पर ध्यान दिया है। सॉलिसिटर जनरल के इस बयान पर कि पत्र की बातों पर पूरी तरह और सही भावना के साथ विचार किया जाएगा, याचिकाकर्ता को अपनी पसंद के ट्रेंड केयरटेकर की मदद 24 घंटे लेने की छूट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खुद को भगवान बताने वाले आसाराम को फिलहाल अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। आसाराम 2013 में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं। कोर्ट ने आसाराम को 24 घंटे मेडिकल मदद के लिए अपनी पसंद का एक ट्रेंड केयरटेकर रखने की इजाज़त दी और कहा कि अगर उनकी सेहत बिगड़ती है, तो वे दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने 31 जुलाई की एम्स रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें कहा गया था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें लगातार मेडिकल मदद की ज़रूरत है।

स्टाइपेंड बढ़ाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने मांगा 3 हफ्ते का समय

इंटर्न डॉक्टर बोले-मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे इंटर्न डॉक्टरों और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बीच देर रात बैठक हुई। मंत्री ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, लेकिन इंटर्न डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि मांग पूरी होने तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे।

स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले चार दिनों से आंदोलनरत छत्तीसगढ़ के इंटर्न डॉक्टरों और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बीच बुधवार देर रात महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में स्टाइपेंड वृद्धि के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए

तीन सप्ताह का समय मांगा और आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित करने की अपील की।बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाने का प्रस्ताव आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शेष औपचारिकताएं जल्द पूरी कर अगले तीन सप्ताह के भीतर सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।

संसद में बड़ा खुलासा

दिल्ली-एनसीआर में दो साल में 254 विदेशी ड्रग तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि एनसीआर में 2024 से लेकर इस वर्ष 30 जून तक मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित मामलों में यहां रहने वाले 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

मंत्री राय ने यह जवाब दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी द्वारा उठाए गए सवालों के उत्तर में दिया।उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार खानपुर एक्सटेंशन, देवली, संगम विहार, महरौली, हौज रानी, उत्तम नगर और पश्चिम दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से इन विदेशी नागरिकों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया। इनमें अधिंकाश नाइजीरियाई नागरिक हैं।उन्होंने बताया कि 103 विदेशी नागरिक बिना अनिवार्य सत्यापन के ही किराये पर घरों में रहते हुए पाए गए। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

पीठासीन अधिकारी की टिप्पणियां स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाई

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक असामान्य फैसले में बुधवार को भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया। पाल ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पारित होने से पहले सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए ये टिप्पणियां की थीं।जगदंबिका पाल ने समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बारे में कुछ बातें कही थीं। ये दोनों 20 जुलाई को संसद तक मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे।जगदंबिका पाल ने समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से सांसद को कार्यवाही में बाधा डालने के लिए टोकते हुए ये टिप्पणियां की थीं। वेणुगोपाल के विरुद्ध जिन टिप्पणियों को हटाया गया, वे भी जगदंबिका पाल ने इसी संदर्भ में की थीं।

पत्रकार तेजपाल को रेप केस में 10 साल की सजा

पणजी, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी पाया और 10 साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है।इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था।मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया।तेजपाल ने कहा- वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ लोग तहलका और राजनीतिक बदले की भावना से 13 सालों से मेरे पीछे पड़े हैं। हमने 7.5 साल ट्रायल कोर्ट में केस लड़ा और बरी हुए थे। मुझे ज्यूडिशियरी पर पूरा भरोसा है कि ऐसे जज होंगे जो सच देखेंगे। हम सबूत सबके सामने पेश करेंगे।तेजपाल के वकील ने कहा, मामला 13 साल पुराना है, उनकी उम्र 62 साल है। उनके खिलाफ कोई दूसरा आपराधिक मामला नहीं है। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महिला पत्रकार ने सबसे पहले तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को ई-मेल भेजकर शिकायत की।

रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

स्कैम वाले विज्ञापनों के जरिए हर साल अरबों डॉलर कमा रहा मेटा

नई दिल्ली। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने बुधवार को सरकार के सामने माना कि खास तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए उसे काफी पैसे दिए गए थे। यह बात तो कम ही सुनने को मिलती है लेकिन ऐसी खबरें आम हैं जिनमें दावा किया जाता है कि अमेरिका की यह कंपनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी कंटेंट होस्ट करके कमाई करती है।

पिछले साल नवंबर में रॉयटर्स ने कंपनी के गुप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी थी कि कंपनी ने पिछले साल ही अंदरूनी तौर पर अनुमान लगाया था कि वह स्कैम और प्रतिबंधित सामानों के विज्ञापन दिखाकर अपनी कुल सालाना कमाई का लगभग 10त्न हिस्सा कमाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटा उन विज्ञापनों की पहचान करने और उन्हें रोकने में नाकाम

रहा, जो धोखाधड़ी वाली ई-कॉमर्स और निवेश योजनाओं, गैर-कानूनी ऑनलाइन कैसीनो और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देते थे।

रॉयटर्स को मिले दिसंबर 2024 के एक दस्तावेज में दावा किया गया है कि जुकरबर्ग की कंपनी ने सोशल मीडिया यूजर्स को हर दिन 15 अरब ज्यादा जोखिम वाले स्कैम विज्ञापन दिखाए। एक और दस्तावेज में बताया गया है कि मेटा को स्कैम विज्ञापनों से हर साल लगभग 7 अरब डॉलर की सालाना कमाई होती थी।

कंटेट फिल्टर में कमी पाई गई

रिपोर्ट में मेटा के आपत्तिजनक कंटेंट फिल्टर में एक कमी बताई गई है। इसमें दावा किया गया है कि कंपनी विज्ञापनदाताओं पर तभी रोक लगाती थी, जब उसके ऑटोमेटेड सिस्टम को धोखाधड़ी का कम से कम 95त्न यकीन हो जाता था।उस समय मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने कहा था कि एजेंसी द्वारा देखे गए दस्तावेज एकतरफा नजरिया पेश करते हैं जो धोखाधड़ी और स्कैम के प्रति मेटा के नजरिए को गलत तरीके से दिखाते हैं। स्टोन ने कहा था, यह आकलन हमारी इंटीग्रिटी से जुड़े उन निवेशों को सही ठहराने के लिए किया गया था जिनकी हमने योजना बनाई थी जिसमें धोखाधड़ी और स्कैम से निपटना भी शामिल है और हमने ऐसा किया भी। उन्होंने कहा, हम धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ सख्ती से लड़ते हैं।

सड़क हादसे में मरा अतीक का सबसे छोटा बेटा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की मौत हो गई। आबान अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। इस इससे पहले 2023 में भी अतीक का एक बेटा

झांसी में ही मारा गया था। वहीं, अतीक और उसके भाई की हत्या प्रयागराज में हुई थी। आइये जानते हैं कभी खौफ का पर्याय रहा अतीक का कुनबा कैसे मिट्टी में मिलता चला गया। 15 अप्रैल 2023 की बात है, अतीक और उसका भाई अशरफ प्रयागराज में थे। उन्हें मेडिकल जांच के लिए पुलिस कॉल्विन अस्पताल ले जा रही थी। जो वीडियो सामने आए, उसके मुताबिक, रात 10 बजकर 30 मिनट से 10 बजकर 50 मिनट का वक्त था। दोनों पुलिस सुरक्षा में चल रहे थे। आगे चार पुलिसकर्मी अत्याधुनिक राइफल के साथ थे। मीडिया के कई माइक दोनों के आगे लगे हुए थे। दोनों एक ही हथकड़ी से बंधे हुए थे। अशरफ दाईं तरफ था। काली टीशर्ट पहनी हुई थी। सिर पर इलाहाबादी गमछा बंधा था। बाईं तरफ अतीक अहमद था। उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ था और हमेशा की तरफ सफेद गमछा बांध रखा था।

भारतीयों को होगी परेशानी... विदेशी फंडिंग कानून पर शशि थरूर ने केंद्र सरकार को घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले विदेशी फंडिंग संशोधन विधेयक, 2026 की तीखी आलोचना की है। थरूर ने आरोप लगाया कि यह यह विधेयक भारतीय राज्य और नागरिक समाज के बीच के संबंधों को मौलिक रूप से बदलने की कोशिश है।

शशि थरूर ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक भारतीय राज्य और नागरिक समाज के संबंधों को पूरी तरह से बदलने और कार्यकारी शक्तियों का केंद्रीकरण करने की एक खतरनाक कोशिश है। इससे भारतीय नागरिक समाज और संस्थानों को परेशानी होगी।

गैर-लाभकारी संस्थाओं पर निशाना: शशि थरूर ने एक अंग्रेजी न्यूज पेपर में अपने लेख में आरोप लगाया, मौजूदा सरकार ने गैर-लाभकारी संस्थाओं, विचारकों और मानवाधिकार समूहों को विकास साझेदारों के बजाय विध्वंस और विदेशी हेरफेर के स्रोत के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक, 2026 सरकार को एक नामित प्राधिकरण बनाने का अधिकार देता है, यह किसी संगठन के एफसीआरए पंजीकरण रद होने, आत्मसमर्पण करने या नवीनीकरण न होने के कारण समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अंशदान और विदेशी अंशदान से निर्मित संपत्तियों के प्रबंधन का कार्यभार संभालेगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि पूजा स्थल जैसी संपत्तियों के मामले में, प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका धार्मिक स्वरूप बरकरार रहे।

बायोफैच इंडिया-2026 में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के विष्णुभोग चावल और केवची के प्राकृतिक शहद ने बटोरी सराहना

छत्तीसगढ़ के जैविक उत्पादों की राष्ट्रीय मंच पर गूंज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, महिला स्वसहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने तथा जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के प्रयास लगातार नई सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-बिहान के अंतर्गत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के महिला स्वसहायता समूहों एवं किसान उत्पादक संगठन द्वारा तैयार किए जा रहे जैविक उत्पादों ने देश के सबसे बड़े एवं प्रतिष्ठित जैविक उद्योग व्यापार मेला एवं सम्मेलन 'बायोफैच इंडिया-2026' में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

नई दिल्ली में आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला एवं सम्मेलन में जिले के प्रसिद्ध 'अरपा बिहान विष्णुभोग राइस' तथा

'केवची के जंगलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद' का राष्ट्रीय स्टॉल में आकर्षक प्रदर्शन किया गया। इन उत्पादों ने देश-विदेश से पहुंचे खरीदारों, निर्यातकों, उद्योग विशेषज्ञों एवं जैविक उत्पादों से जुड़े प्रतिनिधियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। यह उपलब्धि न केवल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली साबित हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा महिला स्वसहायता समूहों की आर्थिक मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी सोच का परिणाम है कि बिहान से जुड़ी महिलाएं आज केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक आयोजनों में अपने उत्पादों का सफल प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रही हैं। इससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि तथा उन्हें स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।बायोफैच इंडिया-2026 प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों तथा मोटे अनाज आधारित कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने वाला विश्वस्तरीय मंच है, जहां देश-विदेश के आयातक, निर्यातक, विपणन विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और व्यापारिक संस्थाएं एकत्रित होकर जैविक उत्पादों के व्यापार एवं निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर छत्तीसगढ़ के उत्पादों की प्रभावी उपस्थिति राज्य के किसानों, महिला स्वसहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए नए व्यापारिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिला मिशन प्रबंधक दुर्गाशंकर सोनी ने बताया कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में जैविक विष्णुभोग धान एवं प्राकृतिक शहद के साथ-साथ सूरन, कटहल तथा अन्य जैविक सब्जियों के उत्पादन को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

बेमेतरा में खाद्य कारोबारियों की जागरूकता बैठक आयोजित, एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर एक वर्ष के लिए लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में बुधवार को जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा होटल व्यवसायियों एवं खाद्य कारोबारियों की जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन खाद्य एवं औषधि नियंत्रक, छत्तीसगढ़ तथा कलेक्टर बेमेतरा के निर्देशानुसार किया गया।

बैठक में जिले के होटल संचालकों, स्वीट शॉप संचालकों, डेयरी व्यवसायियों तथा अन्य खाद्य कारोबारियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। इस दौरान शासन द्वारा जारी आदेशों की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक को संबोधित करते हुए अभिहित अधिकारी श्री आशीष यादव एवं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू कुर्रे ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में एनालॉग पनीर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि एनालॉग पनीर दूध की वसा के स्थान पर वनस्पति वसा अथवा तेल से तैयार किया जाता है तथा कई स्थानों पर इसे सामान्य पनीर के रूप में बेचकर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जाता रहा है। ऐसे उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए शासन ने जनहित में इस पर प्रतिबंध लगाया है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय अथवा उपयोग नहीं किया जाए। निरीक्षण के दौरान यदि किसी होटल, दुकान अथवा प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर पाया जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कारोबारियों से असली पनीर की गुणवत्ता बनाए रखने तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया गया।बैठक के दौरान खाद्य अपमिश्रण की पहचान, खाद्य पदार्थों की सही लेबलिंग, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन सहित सुरक्षित खाद्य व्यवसाय संचालन से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग ने बताया कि जिले में समय-समय पर निरीक्षण, सैंपलिंग एवं जांच की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। बैठक में उपस्थित होटल संचालकों, स्वीट विक्रेताओं, डेयरी संचालकों एवं अन्य खाद्य कारोबारियों ने शासन के निर्णय का स्वागत करते हुए सभी नियमों का पूर्ण पालन करने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला एवं कन्हैयालाल वैदिक कॉन्वेंट स्कूल हसौद के 500 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया

विद्यालयों के 500 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई

सक्ती/मूक पत्रिका

कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती के मार्गदर्शन में तहसील हसौद अंतर्गत कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला एवं कन्हैयालाल वैदिक कॉन्वेंट स्कूल हसौद के 500 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पायल डेली नीड्स, गंगा जनरल स्टोर, मनोज किराना स्टोर, विक्की किराना स्टोर, युवराज जनरल स्टोर, तिरिथराम पान दुकान, जीतू पान दुकान, कान्हा जनरल स्टोर, उमा जनरल स्टोर एवं निखिल पान दुकान में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सहित अन्य नशीले उत्पाद पाए जाने पर संयुक्त दल द्वारा जप्ती की कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानदारों पर अर्थदंड आरोपित किया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार हसौद, हल्का पटवारी हसौद एवं पुलिस बल हसौद की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जिला प्रशासन ने विद्यालयों के आसपास तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहने की बात कही है।

भांजी से जबरन शादी की धमकी देकर चाकू लहराने वाला युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत हुई कार्रवाई..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिले के सलिहा थाना क्षेत्र में युवती से जबरन शादी करने की धमकी देकर चाकू लहराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है।पुलिस के अनुसार ग्राम बानीखार निवासी शरीफ खान (45 वर्ष) ने थाना सलिहा में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 अगस्त 2026 को ग्राम राजादेवरी निवासी आरीफ खान उर्फ राजा (23 वर्ष) उसकी भांजी से जबरदस्ती शादी करने की बात कह रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने हाथ में लंबा चाकू लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज की। शिकायत के आधार पर सलिहा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमिषा पाण्डेय तथा एसडीओपी बिलाईगढ़ विजय कुमार ठाकुर के निर्देशन में थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर जब्त किया। इसके बाद मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी जोड़ दी गई। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा, सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश रजक, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र साव, देवप्रसाद सिदार, निशांत दुबे तथा आरक्षक राजेश नारंग, आनंद पुरेना, चंद्रप्रकाश भारद्वाज सहित सलिहा थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रसव के दौरान 1 भी मातृ और शिशु की मृत्यु नहीं होनी चाहिए : कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू

कलेक्टर ने की स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा

बच्चों को फैलने वाले रोगों के मरीजों से दूर रखने पालकों को समझाने के निर्देश

टीबी और कुष्ठ मुक्त जिला बनाने के लिए बेहतर प्लान के साथ कार्य करने के निर्देश

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने अप्रैल से जुलाई तक की स्थिति में स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का योजनावार, ब्लॉकवार डेटा की जानकारी लेकर सयुंक्त समीक्षा किया। बैठक में डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल, ऋचा सिंह, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, डीपीएम, दोनों विभाग के सेक्टर सुपरवाइजर और सुपरवाइजर उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में कलेक्टर ने कहा कि संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। जिले में 1 भी मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर नहीं होनी चाहिए। दोनों विभाग के अधिकारी कर्मचारी आपस में समन्वय कर कार्य करें। यदि कोई मृत्यु हुई तो जांच होगी। किसी भी कर्मी की सेवा में कमी या लापरवाही हुई तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। हाईरिस्क प्रेग्नेंट महिला और उसके पति को प्रसव के समय आने वाली दिक्कत खून का बहाव, खून की कमी, सामान्य प्रसव या ऑपरेशन से प्रसव आदि स्थिति के बारे में समझाए और प्रसव पीड़ा या गर्भ का समय पूर्ण होने की स्थिति में नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने पोषण पुनर्वास केंद्र में अब तक सुपोषित बच्चों की स्थिति की जानकारी लेकर कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग कुपोषित बच्चों का चयन कर पोषण पुनर्वास केंद्र भेजें, वहीं दर्ज बच्चों को सारी सुपोषण दवा और पोषक आहार प्रदान करें। कलेक्टर ने जिले में पुराने और नये टीबी मरीजों की जानकारी सुपरवाइजरों से लेकर निर्देश दिए कि, सभी अपने क्षेत्र के टीबी मरीजों को समझाये कि, वे जब किसी व्यक्ति के आसपास मौजूद होते हैं तो वे मास्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि टीबी और कुष्ठ रोग दोनों एक दूसरे के माध्यम से फैलता है इसलिए बच्चों सहित अन्य लोग खानपान में सावधानी रखें। सभी मरीजों को नियमित दवा खाने की समझाइश दें। टीबी और कुष्ठ बीमारी को खत्म करने के लिए सभी घरों में बीमार व्यक्ति से बच्चों को दूर रखें, जिले में 8 बच्चों को कुष्ठ बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। कुष्ठ बीमारी के लक्षण आने में 3 से 5 साल का समय लगता है। कलेक्टर ने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए 15 वर्ष के बालिकाओं और अन्य इच्छुक महिलाओ को एचपीवी वैक्सीन लगाने के लिए पालकों को प्रेरित करें।कलेक्टर ने पीएम बाल संदर्भ चिरायु और पीएम मातृ वंदना योजना के अब तक हुए शिविर की जानकारी लेकर कहा कि पीएम मातृ वंदना योजना के अब तक 1883 को लाभ मिला है वहीं कुल 1981 में से 126 हितग्राहियों के सत्यापन और अप्रूवल लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करें। स्कूल और बच्चों की सूची एक दूसरे को उपलब्ध कराएं। टीबी और कुष्ठ मुक्त जिला बनाने के लिए बेहतर प्लान के साथ कार्य करें।

खेती में तकनीक का उपयोग: किसानों ने ड्रोन से खरपतवार नाशक का छिड़काव कर 40 हेक्टेयर में बचाया समय और श्रम

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे / जिले के किसान अब खेती में तकनीक का इस्तेमाल कर आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड भाटापारा के ग्राम पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसानों ने खेती में तकनीक का नया उदाहरण पेश किया है। यहां करीब 40 हेक्टेयर रकबे में किसानों ने ड्रोन के माध्यम से खरपतवार नाशक का छिड़काव करवाया। पारंपरिक तरीके से इस रकबे में छिड़काव करने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। ड्रोन की मदद से पूरा काम कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। इससे किसानों के समय, श्रम और लागत तीनों की बचत हुई।ग्राम धौरभठा के किसान आलोक जायसवाल एवं खोलवा के कृषक गुड्डू चांडक ने बताया कि पहले 2से 3 एकड़ में छिड़काव करने के लिए 2 मजदूर पूरे दिन लगते थे। ड्रोन से 40 हेक्टेयर का काम एक दिन में हो गया। पानी भी कम लगी और पीठ पर टंकी ढोने की परेशानी नहीं रही।कृषि विभाग और स्थानीय कृषि तकनीक सेवा प्रदाता के सहयोग से ड्रोन को खेतों में उतारा गया। ड्रोन ने निर्धारित ऊंचाई से एक समान रूप से खरपतवार नाशक का छिड़काव किया। इससे दवा की बर्बादी भी कम हुई और फसल पर असर बेहतर रहा।मैनुअल छिड़काव की तुलना में 80 प्रतिशत समय कम लगा। इसके साथ ही मजदूरी और दवा दोनों में बचत एवं एक समान छिड़काव से खरपतवार नियंत्रण बेहतर हुई। जिला प्रशासन द्वारा सहकरी समिति के माध्यम से किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें 4 नग ईफ्को कम्पनी के भी है।

कृषि विभाग के अधिकारियो ने बताया कि इस व्यवस्था से अब छोटे किसानों को भी कम दर पर ड्रोन सेवा मिल रही है। भाटापारा क्षेत्र में धान और दलहन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए यह तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है।फिलहाल पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसान इस प्रयोग से काफी संतुष्ट हैं और आने वाले सीजन में और अधिक रकबे में ड्रोन से छिड़काव करवाने की योजना बना रहे हैं।

90 लाख 28 हजार का धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफास, महिला एवं पुरुष आरोपी की 24 घण्टे के भीतर की गई गिरफ्तारी

सक्ती/बाराद्वार/मूक पत्रिका

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मूलचंद राठौर पिता धनीराम राठौर उम्र 48 वर्ष मूल निवासी ग्राम मल्दी थाना सक्ती हाल मु. ग्राम जेठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती द्वारा दिनांक 05.05.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि पेण्ड्रा निवासी रेखा राठौर, पुष्पांजली राठौर, अफरोज खान एवं सुभाष साहू के द्वारा सोना नवनीकरण एवं ऋण अवधी को आगे बढ़ाने की लालच देकर संगठित होकर षड़यंत्र कर प्रार्थी के एवं उसके पत्नि, पुत्र के विभिन्न बैंक खातों एवं यूपीआई नेफ्ट आरटीजीएस आइएमपीएस के माध्यम से रेखा राठौर, अफरोज खान, सुभाष साहू के द्वारा अपने अकाउंट नंबरो में ट्रांसफर करा कर 90 लाख 28 हजार 5 सौ रूपये बेईमानी से उत्प्रेरित कर ठगी किया गया। उक्त गंभीर अपराध को संज्ञान में लेते हुए थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 282/2026 धारा 318(4), 61(2), 112 भारतीय न्याय संहिता (ठछै) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता के देखते हुए पुलिस अधीक्षक सक्ती को अगवत कराया गया। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर राम गोपाल गर्ग, प्रफुल्ल कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक (भा.पु.से.) जिला सक्ती के मार्गदर्शन तथा पंकज पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती एवं भुनेश्वरी पैंकरा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सक्ती के कड़े पर्यवेक्षण में थाना बाराद्वार प्रभारी नरेन्द्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर तत्काल आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना किया गया। रवाना किये गये विशेष पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध घेराबंदी एवं दबिश देकर 01 महिला आरोपी एवं 02 पुरूश आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उक्त तीनों आरोपिओ द्वारा रूपये कमाने के मकसद से संगठित होकर योजना बनाकर लम्बी रकम कमाने के लिए जेठा निवासी मूलचंद राठौर को सोना नवनीकरण एवं ऋण अवधी बढ़ाने का लालच देकर दिनांक 31.10.2025 से दिनांक 05.05.2026 तक ग्राम जेठा निवासी मूलचंद राठौर, मूलचंद राठौर की पत्नि फुलबाई राठौर, मूलचंद राठौर का बड़ा लड़का सुभाश सिंह राठौर, छोटा लड़का विनय सिंह राठौर के अलग-अलग सेविंग/करेंट खाता नम्बरों से, यूपीआई, एनटीएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के माध्यम से 90 लाख 28 हजार 5 सौ रूपये का धोखाधडी कर ठगी कराना स्वीकार किया गया। थाना बाराद्वार जिला सक्ती पुलिस यह स्पष्ट करती है कि धोखाधड़ी, लूट, डकैती एवं अन्य संगीन अपराधों में संलिप्त अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। जिला पुलिस सक्ती नागरिकों की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

महिलाओं समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने किया विरोध, विधायक विक्रम मंडावी पहुंचे समर्थन में; प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील

संगमपल्ली में शराब दुकान के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रस्ताव वापस लेने की मांग

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। भोपालपटनम विकासखंड के ग्राम संगमपल्ली (मद्देड) में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान के विरोध में गुरुवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर दुकान हटाने की मांग उठाई। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्गों ने ग्रामसभा की सहमति के बिना शराब दुकान खोले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे गांव में नशाखोरी बढ़ेगी और सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से प्रस्ताव तत्काल निरस्त करने की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।ग्रामीणों ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देने के बजाय शराब दुकानें खोली जा रही हैं। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने आशंका जताई कि दुकान खुलने से घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उनका कहना था कि इसका असर परिवारों की आर्थिक स्थिति और खेती-किसानी पर भी पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान विधायक विक्रम मंडावी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने प्रशासन से ग्रामीणों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार कर प्रस्तावित शराब दुकान का निर्णय वापस लेने की अपील की। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र चापा, सरिता चापा, सुनील उद्दे, मनोज यालम, तलांडी इस्तारी, पुरुषोत्तम सल्लूर, सुरेश सोढ़ी, गुड्डू कोरसा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

विधायक का बयान

प्रदर्शन के दौरान विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के बजाय सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे आदिवासी युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा। विधायक ने प्रशासन से संगमपल्ली में प्रस्तावित शराब दुकान का निर्णय तत्काल निरस्त करने और ग्रामीणों की भावनाओं का सम्मान करने की मांग की।

ग्रामीणों की प्रमुख आपत्तियां

- ग्रामसभा की सहमति के बिना शराब दुकान खोले जाने का आरोप।- शराब दुकान से नशाखोरी और सामाजिक समस्याएं बढ़ने की आशंका।- महिलाओं ने घरेलू हिंसा और खेती-किसानी पर असर की चिंता जताई।
- मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी।

चिरायु योजना बनी बच्चों के लिए जीवनदायिनी, जन्मजात विकृतियों से पीड़ित तीन बच्चों का हुआ नि:शुल्क सफल उपचार

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोग एवं कटे-फटे होंठ-तालु से ग्रसित बच्चों को मिला नया जीवन, आयुष्मान भारत योजना के समन्वय से संभव हुआ उपचार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु योजना) बेमेतरा जिले में जन्मजात विकृतियों से पीड़ित बच्चों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। योजना के माध्यम से जन्मजात हृदय रोग एवं कटे-फटे होंठ-तालु जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे तीन बच्चों का निःशुल्क सफल उपचार कर उन्हें स्वस्थ जीवन की नई शुरुआत दी गई।कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृतलाल रोहलेडर के मार्गदर्शन में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. शरद कोहाड़े, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री लता बंजारे एवं सहायक जिला नोडल अधिकारी डॉ. ऋषभ शर्मा के समन्वित प्रयासों से चिरायु योजना एवं आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। योजना के तहत दो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों एवं एक कटे-फटे होंठ-तालु से ग्रसित बच्ची का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क सफल

ऑपरेशन कराया गया।

प्रेरणा साहू के दिल का सफल ऑपरेशन, मिला स्वस्थ जीवन-ग्राम झिरिया, विकासखंड बेमेतरा निवासी कु. प्रेरणा साहू, पिता परमानंद साहू, जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थीं। 23 मई 2026 को आंगनबाड़ी केंद्र झिरिया में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चिरायु दल ने बच्ची के हृदय में असामान्य ध्वनि (मर्मर साउंड) की पहचान की। विशेषज्ञ जांच (ईको) में हृदय में छेद की पुष्टि होने पर परिजनों को योजना की जानकारी देकर उपचार के लिए प्रेरित किया गया। 20 जुलाई 2026 को बच्ची को उच्च चिकित्सा संस्थान में भर्ती कराया गया तथा 28 जुलाई 2026 को सफल हृदय ऑपरेशन किया गया। वर्तमान में प्रेरणा पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जीवन जी रही है।

रिशिका पाल का निःशुल्क हृदय उपचार बना नई उम्मीद-बेमेतरा नगर के वार्ड क्रमांक-09 निवासी कु. रिशिका पाल, पिता बंशी पाल, भी गंभीर जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थीं। आंगनबाड़ी भ्रमण के दौरान चिरायु दल ने बच्ची की पहचान की। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण परिजन उपचार कराने में असमर्थ थे। चिरायु योजना के तहत निःशुल्क इलाज का भरोसा दिलाकर बच्ची को उच्च चिकित्सा संस्थान भेजा गया। 20 मई 2026 को भर्ती करने के बाद 22 मई 2026 को सफल हृदय ऑपरेशन किया गया। उपचार के बाद रिशिका अब स्वस्थ एवं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है।

तरणी चंद्राकर की मुस्कान लौटी-ग्राम कोदवा, विकासखंड बेमेतरा निवासी कु. तरणी चंद्राकर, पिता सोनलाल चंद्राकर, जन्मजात कटे-फटे होंठ-तालु की विकृति से पीड़ित थीं। चिरायु दल ने बच्ची का चिन्हांकन कर उच्च चिकित्सा संस्थान में रेफर किया, जहाँ 11 जुलाई 2026 को प्रथम चरण में कटे-फटे होंठ का निःशुल्क सफल ऑपरेशन किया गया। उपचार के बाद बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और आगे के उपचार की प्रक्रिया भी जारी है। चिरायु योजना के अंतर्गत बच्चों की समय पर पहचान, विशेषज्ञ जांच, रेफरल एवं निःशुल्क उपचार की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है।

योजना के माध्यम से जिले में लगातार ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिरायु दल के सदस्य डॉ. अभिषेक यादव, डॉ. दिलीप चंद्रवंशी, डॉ. प्रीति ठाकुर, डॉ. ज्योति वर्मा, हिना सिन्हा, खिलेन्द्र साहू, बलवंत बंजारे, सत्यवीर डंडोतिया, मनीष साहू, दीपा विश्वकर्मा एवं आरती वर्मा की महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका रही। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे बच्चों का सतत चिन्हांकन कर उन्हें चिरायु योजना एवं आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से निःशुल्क उपचार का लाभ दिलाया जाता रहेगा।

एनएच 130 पर इनोवा को यात्रियों से भरी बस ने मारी टक्कर, एक महिला की मौत

ग्राम जजगा में हुई घटना, आधा दर्जन लोग घायल, जांच जारी

अम्बिकापुर। एनएच 130 पर यात्री बस ने इनोवा कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के समय परिवार बिलासपुर से कफन दफन से वापस लौट रहा था। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। मामले में पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिले के लुंड्रा के ग्राम लमगांव स्कूल पारा निवासी आसन लाल तिग्गा अपनी पत्नी दिलीप कुमारी तिग्गा व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 5 अगस्त को इनोवा वाहन क्रमांक सीजी 15 ईडी 9050 बिलासपुर में अपने रिश्तेदार के घर कफन दफन में शामिल होने गया था। इस दौरान 6 अगस्त को भोर में सभी वापस लौट रहे थे। इस दौरान भोर में लगभग 5 बजे एनएच 130 पर जजगा रामपूरहिन मन्दिर एवं राजवाड़े

ढाबा के बीच इनोवा को पापुलर बस कमांक सीजी 15 डीएम 0186 ने टक्कर मार दी। टक्कर इनती जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद इनोवा के एयरबैग भी खुले लेकिन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना में महिला दिलीप कुमारी तिग्गा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति आसन लाल तिग्गा को गंभीर चोट आई है। आसन लाल तिग्गा के कमर पैर, सेवक टोप्पो के दाहिने सीने के पास व पैर, शिवकिर्तन के सीने में, अगस्तुक बड़ा के सीना मे, असीकुनिया के सीने पैर हाथ, सोभनाथ के आंख के भौं पास व सीना में तथा इनोवा कार चालक विजय सीना पैर हाथ में गंभीर चोट आई है। सभी घायलों को उपचार के लिए लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रिफर कर दिया गया है। इसके साथ ही मामले में पुलिस ने लाश को पीएम उपरान्त परिजन के सुपुर्द कर दिया। मामले में लखनपुर पुलिस द्वारा बस चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

संत रविदास की जन्मस्थली की पावन मिट्टी से युक्त कलश एवं रथ का सरगुजा में भव्य स्वागत

अम्बिकापुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित कलश वंदन एवं वितरण समारोह से प्राप्त संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) की पावन मिट्टी से युक्त कलश एवं रथ के सरगुजा आगमन पर भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक पूजन-अर्चन एवं स्वागत किया। इसके उपरांत पवित्र कलश एवं रथ को नगर स्थित श्री हनुमान मंदिर में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया। संत रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर यह पवित्र कलश जिले के विभिन्न मंडलों एवं ग्रामों में भ्रमण करेगा तथा उनके सामाजिक समरसता, समानता एवं मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बनेगा। इस दौरान महापौर मंजूषा भगत, फुलेश्वरी सिंह, विनोद हर्ष, मधु चौदाहा, निश्चल प्रताप सिंह, शुभांगी बिहाडे, ममता कश्यप , शोभा शर्मा , बबलू गुप्ता, सावित्री जयसवाल, शकुंतला पांडे,नीलम राजवाड़े, बबली नेताम, रजनी बिंद, रश्मि जयसवाल, प्रियंका चौबे, नीलू गुप्ता,अर्चना सिंह, रेनू भारती, सरस्वती यादव, शालिनी सिंह, रीना राय, नलिनी पांडे, रूपा गुप्ता, पंकज गुप्ता, रवि विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे ।

मिशन उत्कर्ष के तहत जिले के सभी हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में मासिक टेस्ट शुरू

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे। जिले में शिक्षा की गुणवता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने एवं बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने के उ?द्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा संचालित मिशन उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 5 अगस्त 2026 से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रथम मासिक टेस्ट प्रारम्भ किया गया है। यह परीक्षा कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले के सभी शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में एक साथ आयोजित की जा रही है।

मिशन उत्कर्ष जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, वि?द्यार्थियों की विषयगत समझ विकसित करने तथा बोर्ड परीक्षाओं

की प्रभावी एवं व्यवस्थित तैयारी कराने के उद्देश्य से संचालित एक महत्वाकांक्षी अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत वि?द्यार्थियों की नियमित शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मासिक परीक्षाओं की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। प्रथम मासिक टेस्ट इसी श्रृंखला की पहली कड़ी है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन कर आवश्यक शैक्षणिक सुधार की दिशा में कार्य किया जाएगा।जिले के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों एवं प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी द्वारा बोर्ड परीक्षा के ब्लूप्रिंट एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्नपत्र तैयार किए गए हैं। परीक्षा के पश्चात उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों को उनकी विषयवार उपलब्धियों एवं कमियों से अवगत कराया जाएगा, जिससे वे समय रहते आवश्यक सुधार कर सकें। जिन विद्यार्थियों को किसी विषय में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होगी, उनके लिए विशेष मार्गदर्शन एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सभी प्राचार्यों, शिक्षकों, वि?द्यार्थियों एवं अभिभावकों से मिशन उत्कर्ष को जन-आंदोलन के रूप में सफल बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने सभी विद्यालयों को परीक्षा का निष्पक्ष, व्यवस्थित एवं समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।मिशन उत्कर्ष के माध्यम से जिला प्रशासन का लक्ष्य केवल बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित शैक्षणिक मार्गदर्शन तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना भी है।

स्कूल-आंगनबाड़ी के पास रातों-रात डंप हुआ दो हाईवा डस्ट, ग्रामीणों में आक्रोश, जांच की मांग

खरसिया/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत चपले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के समीप रातों-रात दो हाईवा डस्ट डंप किए जाने का मामला सामने आया है। बुधवार सुबह जब ग्रामीणों ने गांव की बीच गली में प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और 2 के पास डस्ट का बड़ा ढेर देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से जांच की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार, अज्ञात लोगों द्वारा देर रात हाईवा वाहनों से डस्ट लाकर डंप किया गया। जिस स्थान पर डस्ट गिराया गया है, वहां से कुछ ही दूरी

पर नहर, दो तालाब और गांव का देवस्थल स्थित है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में डस्ट गांव के बीच कैसे पहुंच गया और इसकी जानकारी पंचायत या जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि जिस स्थान पर डस्ट डंप किया गया है, वहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और आंगनबाड़ी के नौनिहाल गुजरते हैं। डस्ट से उड़ने वाली धूल बच्चों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वहीं बारिश के दौरान इसके बहकर नहर और तालाब में पहुंचने से पर्यावरण प्रदूषण की भी आशंका जताई जा रही है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो डस्ट डंप कराने वाले वाहन और जिम्मेदार लोगों की पहचान आसानी से हो सकती है। लोगों ने प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग से मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफसख्त कार्रवाई करने की मांग की है।फिलहाल पूरे मामले को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और ग्रामीण प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।

आपसी विवाद में कैंची से पेट में वार कर युवक की हत्या करने वाला आरोपी कसडोल पुलिस की तत्परता से गिरफ्तार!

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय (ढ्ढक्क्र) द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में थाना कसडोल पुलिस ने हत्या के मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्क्स्हरु ऑफिस कसडोल के पास मामूली विवाद पर कैंची से पेट में ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ?घटनाक्रम एवं प्राथमिकीः- दिनांक 05.08.2026

को प्रार्थी का पुत्र (मृतक अजय पैकरा) एवं आरोपी फिरतु यादव के बीच क्क्स्हरु ऑफिस के पास किसी बात को लेकर विवाद एवं गाली-गलौज हुई। इसी दौरान आरोपी फिरतु यादव ने रंजिशवश ÷तू जब भी मुझसे मिलता है बहुत ज्यादा बात करता है, आज तेरे को निपटा दूंगा÷ कहते हुए जान से मारने की नीयत से अपने पास रखी धारदार कैंची से अजय पैकरा के पेट में गंभीर वार कर दिया। ?पेट में गंभीर चोट लगने के कारण अजय पैकरा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों द्वारा उसे तत्काल शासकीय अस्पताल कसडोल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के उपरांत गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल बलौदाबाजार रेफर किया गया। एम्बुलेंस से ले जाते समय रास्ते में ही अत्यधिक रक्तस्राव एवं गंभीर चोट के कारण अजय सिंह पैकरा की मृत्यु हो गई। पुलिस की त्वरित विवेचना एवं साक्ष्य जप्तीः- ?प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कसडोल में अपराध क्रमांक 299/2026 धारा 103(1) क्क्हस् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना कसडोल पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर संदेही आरोपी फिरतु यादव को अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। ?गवाहों के समक्ष आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त धारदार कैंची एवं घटना के समय पहना हुआ टी-शर्ट विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। ?आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर उसे दिनांक 06.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

बिंजकोट-दर्रामुड़ा से बड़े जामपाली और कुरूभांठा मार्ग तक ट्रांसपोर्टरों की मनमानी से दहशत, ग्रामीण बोले– हादसे से पहले लगे लगाम

ऐश डाईक में चंद्रा क्रशर उद्योग की निजी पोकलेन से धड़ल्ले से ओवरलोडिंग, बेकाबू रफ्तार और उड़ती फ्लाई ऐश ने बढ़ाया खतरा

खरसिया/मूक पत्रिका

बिंजकोट दर्रामुड़ा इलाके में इन दिनों राह चलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। सड़कों पर बेधड़क दौड़ती ओवरलोड गाड़ियाँ, हवा में तैरता राख का गुबार और हर पल मँडराता हादसे का ख़तरा अब यहाँ के लोगों की रोज़ की नियति बन चुका है। कागज़ों पर भले ही नियम-कायदों की दुहाई दी जाती हो, लेकिन ज़मीन पर ट्रांसपोर्टरों की मनमानी और कमाई की अंधी दौड़ ने पूरे इलाक़े का जीना दूभर कर दिया है।स्थानीय लोगों का साफ़ कहना है कि मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के ऐश डाईक से बड़े पैमाने पर उड़न-राख यानी फ्लाई ऐश उठाई जा रही है। लेकिन इस काम में लगे ठेकेदारों को न तो लोगों की सलामती की परवाह है और न ही प्रशासन के ख़ौफ़ का। गाड़ियों में क्षमता से कई गुना ज़्यादा

राख ठूँस-ठूँसकर भरी जा रही है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाए जा सकें। इस होड़ में गाड़ियाँ सड़कों पर फर्राटा भरती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं राख का ऐसा गुबार, जिसमें सामने का रास्ता तक दिखना बंद हो जाता है।

चंद्रा क्रशर का दबदबाः तीन-तीन पोकलेन उतारकर नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियाँ-इस पूरे खेल के पीछे सबसे बड़ा नाम चंद्रा क्रशर उद्योग का सामने आ रहा है। चर्चा है कि ऐश डाईक के अंदर नियमों को ताक पर रखकर निजी पोकलेन मशीनों का जाल बिछा दिया गया है। सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अकेला चंद्रा क्रशर उद्योग वहाँ धड़ल्ले से अपनी तीन-तीन भारी-भरकम पोकलेन मशीनें चला रहा है, जबकि एक अन्य मशीन किसी दूसरे ठेकेदार की है। दिन हो या रात, बिना किसी रोक-टोक के इन मशीनों से हाईवा में ओवरलोडिंग का खेल जारी रहता है। सुरक्षा मानकों को हवा में उड़ाते हुए जिस तरह चंद्रा क्रशर उद्योग डंपरों को ऊपर तक भर रहा है, उससे साफ़दिखता है कि यहाँ नियम-कानूनों की धज्जियाँ उड़ाने की खुली छूट मिली हुई है।

सड़क पर जब इन गाड़ियों को रोका जाता है या चालकों से बात होती है, तो कई अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों के नाम सामने आते हैं। श्री दाऊजी इंटरप्राइजेज, आदिशक्ति, आशीर्वाद ट्रेडिंग, छाल ट्रांसपोर्ट, आई एंड यू, जिंदल कंस्ट्रक्शन, अनुप रोड, मां अंबे, श्रीजी सर्विस, सृष्टि और सत करतार जैसे दर्जनों नाम इस कारोबार में शामिल हैं। लेकिन इन सब में चंद्रा क्रशर की मनमानी का दबदबा सबसे ज़्यादा नज़र आता है, जिसकी पोकलेन मशीनें दिन-रात बिना किसी डर के डाईक पर गर्जना कर रही हैं।

गर्मी में धुंधलाता रास्ता, बारिश में बिछती मौत की फिसलन-मौसम चाहे जो भी हो, इस मार्ग से गुज़रने वाले राहगीरों के लिए आफ़त कम नहीं होती। गर्मी और सूखे के दिनों में गाड़ियों से झड़ती राख हवा में फैलकर पूरे इलाके को धूल के आगोश में ले लेती है। दोपहिया वाहन चालकों की आँखों में अचानक राख भर जाती है, जिससे गाड़ियाँ अनियंत्रित होकर गिर पड़ती हैं। वहीं, हल्की सी बारिश होते ही सड़क पर बिछी यह राख पानी से मिलकर ऐसा दलदल और फिसलन बनाती है कि गाड़ियाँ ज़मीन पर साबुन की तरह फिसलने लगती हैं। आए दिन बाइक सवार और छोटे वाहन इस चिकनी सड़क पर हादसे का शिकार हो रहे हैं।

मीलों लंबी कतारें, घंटों ठप रहता है जनजीवन-समस्या सिर्फ़ उड़ती राख तक सीमित नहीं है। बिंजकोट-दर्रामुड़ा से लेकर बड़े जामपाली और कुरूभांठा तक सड़कों के दोनों ओर खड़े भारी-भरकम हाईवा वाहनों का कब्ज़ा रहता है। गाड़ियों की इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं कि रास्ता पूरी तरह छेक लिया जाता है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हों, दफ़्तर निकलने वाले नौकरीपेशा या फिर कोई बीमार मरीज, हर कोई इन गाड़ियों के बनाए जाम में घंटों फँसने को मजबूर है। कई जगहों पर तो पैदल चलने तक की जगह नहीं बचती।

सब्र का बाँध टूटने से पहले जागे प्रशासन, ग्रामीणों ने की कड़ी कार्रवाई की माँग-इलाके के लोगों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते इस ओवरलोडिंग, अंधाधुंध रफ़्तार और चंद्रा क्रशर उद्योग जैसी कंपनियों की दादागीरी पर नकेल नहीं कसी गई, तो यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने साफ़ शब्दों में माँग की है कि ऐश डाईक में चल रही निजी मशीनों की जाँच की जाए, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का वज़न नापा जाए और नियम तोड़ने वाले ट्रांसपोर्टरों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतज़ार करता है या फिर समय रहते इन बेकाबू ट्रांसपोर्टरों पर लगाम कसता है।

संपादकीय

पीओके में सरकारी दमन हो रहा है, दखल दे दुनिया

भारत ने पीओके में सरकारी दमन रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है। पाकिस्तानी सरकार की कार्रवाई में 40 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। भारत ने कहा कि यह कार्रवाई अस्वीकार्य है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में सरकारी दमन रोकने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है, जो वहां के हालात को देखते हुए बिल्कुल सही है। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार की कार्रवाई में पीओके में 40 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि वहां लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।चुनाव से जुड़ा है विरोध। यह मामला वहां हो रहे चुनावों से जुड़ा है। पीओके में 45 सीटों के लिए असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। ये चुनाव तीन चरणों में कराए जा रहे हैं, जो 10 अगस्त को पूरे होंगे। यहां विधानसभा की 53 सीटें हैं। इनमें से 45 पर सीधा चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रैट्स और धर्मगुरुओं के लिए आरक्षित हैं। जबरदस्त धांधली हुई। 27 जुलाई को पहले चरण का चुनाव हुआ। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) ने 13 में से 9 सीटें जीतीं, बाकी 4 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलीं। इस चरण में जबरदस्त धांधली हुई। यह बात भी छिपी नहीं है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की है। वह मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करता आया है। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान की ज्यादतियों की खबरों से दुनिया अनजान नहीं है। पिछले दो महीने से पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन उन 12 सीटों को लेकर हो रहे हैं, जो प्रवासियों के लिए आरक्षित हैं। इसकी अगुआई जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी नाम का सिविल सोसाइटी ग्रुप कर रहा है। जेएएसी का कहना है कि इस्लामाबाद सरकार इन सीटों पर धांधली कर अपने लोग बिठाती है ताकि पीओके असेंबली पर उसका कंट्रोल बना रहे।इस आरोप में दम है क्योंकि जो पार्टी पाकिस्तान पर हुकूमत करती है, वही अक्सर पीओके चुनाव जीतती है। इसी वजह से 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) और 2021 में इमरान खान की पार्टी को यहां जीत मिली। मगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों के गुस्से की वजहें सिर्फ चुनावी धांधली ही नहीं हैं। आर्थिक दुश्वारियों की वजह से भी उनमें गुस्सा है। फिर स्थानीय लोगों के अधिकार और भी सीमित किए जा रहे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि सरकारी बंदिशों की वजह से इलाके में लोगों को सब्सिडाइज्ड गेहूं और जरूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। बिजली कटौती को लेकर भी लोगों में गुस्सा है।पाक अधिकृत कश्मीर की नदियों पर बने हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स से जो बिजली बनती है, वह यहां के लिए जरूरी 400 मेगावॉट से कहीं अधिक है। इसके बावजूद इलाके में 15-20 घंटों तक बिजली काटी जाती है।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों पर मोदी सरकार के तर्कपूर्ण जवाब

(नीरज कुमार दुबे)

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क का जोरदार प्रतिवाद किया। उन्होंने अदालत से कहा कि बहस की शुरुआत इस धारणा से नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर ऐसी बहस छिड़ी, मानो लोकतंत्र की सबसे अहम संस्थाओं में से एक का भविष्य न्यायालय के कटघरे में खड़ा हो। एक ओर संविधान की आत्मा और निष्पक्ष चुनाव की कसौटी पर सवाल उठाते न्यायाधीश थे तो दूसरी ओर संसद की सर्वोच्चता और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पक्ष मजबूती से रखती केंद्र सरकार। सवालों और जवाबों का यह सिलसिला कई बार अदालत की बहस से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणाओं पर गहन विमर्श में बदल गया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले यही सवाल उछाला कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का पद लोकतंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर उनके चयन की प्रक्रिया ऐसी क्यों न हो, जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह न रहे? अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र होकर काम करे, इतना पर्याप्त नहीं है; उसे स्वतंत्र दिखाई भी देना चाहिए।

इसी संदर्भ में अदालत ने सरकार से सीधा प्रश्न किया कि संसद ने 2023 का कानून बनाते समय चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने का निर्णय आखिर किस आधार पर लिया? पीठ ने याद दिलाया कि सीबीआई निदेशक और लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों के चयन में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका स्वीकार की गई है, फिर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के मामले में यह व्यवस्था क्यों बदली गई?

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क का जोरदार प्रतिवाद किया। उन्होंने अदालत से कहा कि बहस की शुरुआत इस धारणा से नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा और पवित्रता है तथा जनता को उनके निर्णयों पर विश्वास होना चाहिए। तुषार मेहता ने सवालिया अंदाज में कहा, यदि प्रधानमंत्री के फैसलों पर भरोसा ही नहीं किया जाएगा, तो क्या फिर मंत्रिमंडल के गठन के समय भी किसी पूर्व न्यायाधीश या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेना अनिवार्य कर दिया जाए?

उन्होंने यह भी दलील दी कि केवल इसलिए कि कार्यपालिका के पास संख्यात्मक बहुमत है, यह मान लेना उचित नहीं कि वह संविधान विरोधी या दुर्भावनापूर्ण निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के तीनों अंग यानि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं और एक संस्था दूसरी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

लेकिन अदालत ने तुरंत स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य प्रधानमंत्री पर अविश्वास जताना नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का है जो जनता के विश्वास की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा, हम यह नहीं कह रहे कि वर्तमान समिति ने निष्पक्षता नहीं बरती है। लेकिन जैसे न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, उसी प्रकार चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में भी निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए।

इसी दौरान अदालत ने सरकार से एक और तीखा सवाल पूछा। पीठ ने याद दिलाया कि पहले भी अदालत ने निर्वाचित सरकार पर भरोसा जताते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री न बनाने की अपेक्षा की थी। ऐसे में आज सरकार में कितने मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं? इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी तय होती है।

हम आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 2023 के उस कानून को लेकर है, जिसके तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री वाली चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

हम आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 2023 के उस कानून को लेकर है, जिसके तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री वाली चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। बाद में संसद ने कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी अदालत से कहा कि संसद की विधायी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। उनका कहना था कि केवल इसलिए कि कोई दूसरा मॉडल बेहतर हो सकता है, संसद द्वारा चुनी गई व्यवस्था को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संसद को इस प्रकार बाधित नहीं किया जा सकता।

सरकार ने अपने हलफनामे में भी यही रुख दोहराया। केंद्र ने कहा कि यह आशंका पूरी तरह काल्पनिक है कि चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका होने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता स्वतः प्रभावित हो जाएगी। सरकार ने याद दिलाया कि सात दशक से अधिक समय तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह कार्यपालिका द्वारा होती रही, लेकिन इस दौरान देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी बाधित नहीं हुए। इसलिए केवल आशंकाओं के आधार पर कानून को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता।

सुनवाई के दौरान केंद्र ने यह आग्रह भी किया कि मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं, इसलिए इसे बड़ी संविधान पीठ को भेजा जाए। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता डी. शेषाद्रि नायडू, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण और संजय पारिख ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि लगभग 20 दिन तक विस्तृत सुनवाई चलने के बाद अब इस आधार पर मामला बड़ी पीठ को भेजने की मांग करना केवल सुनवाई को टालने का प्रयास है।

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की गई है। अब निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह निर्णय केवल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, संसद की विधायी शक्ति और जनता के भरोसे के बीच संतुलन की नई संवैधानिक रेखा भी खींच सकता है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026

39 मेडल जीते, इतिहास भी रचा, लेकिन इन 5 खेलों ने बढ़ाई भारत की चिंता

(आलोक श्रीवास्तव)

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण समेत कुल 39 पदक जीतकर चौथे नंबर पर रहा। बॉक्सिंग और जूडो ने इतिहास रचा, लेकिन पांच खेल ऐसे रहे जहां भारत एक भी पदक नहीं जीत पाया। जानिए भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियां और सबसे बड़ी चिंताएं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 39 पदक जीतकर इतिहास रचा और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। बॉक्सिंग ने रिकॉर्ड 7 स्वर्ण दिलाए, जूडो में पहली बार दो गोल्ड आए, जबकि पैरा एथलेटिक्स ने 20 साल बाद पदक का सूखा खत्म किया। हालांकि, इन तमाम उपलब्धियों के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता उन पांच खेलों ने बढ़ा दी, जिनमें एक भी पदक नहीं आया। इनमें आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, ट्रैक साइक्लिंग, लॉन बाउल्स और 3म3 बास्केटबॉल शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन खेलों में भारत लगातार निवेश और तैयारी बढ़ा रहा है, वहां नतीजे अब भी क्यों नहीं मिल रहे?

बॉक्सिंग ने अकेले दिलाए आधे से ज्यादा गोल्ड – भारत के लिए इस बार सबसे बड़ा आकर्षण मुक्केबाजी (बॉक्सिंग) रही। देश के मुक्केबाजों ने 14 में से 10 पदक जीते। इनमें सात स्वर्ण पदक हैं। यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में बॉक्सिंग में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने किसी एक संस्करण में अधिकतम तीन स्वर्ण पदक जीते थे। प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, जैसमीन लम्बोरिया, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीतकर भारतीय मुक्केबाजी की नई पीढ़ी की ताकत दिखा दी।

जूडो ने पहली बार लिखा स्वर्णिम इतिहास – कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो भारत के लिए कभी बड़ा पदक देने वाला खेल नहीं रहा था। हालांकि, ग्लासगो में तस्वीर बदल गई। अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इस उपलब्धि को और बड़ा बना दिया। भारत ने जूडो में कुल चार पदक जीते। इनमें दो स्वर्ण पदक शामिल रहे।

पैरा एथलेटिक्स ने खत्म किया 20 साल का इंतजार – भारत के लिए पैरा एथलेटिक्स से भी बड़ी खुशखबरी आई। शार्मिला ढांकर, दिलीप गावित और सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीतकर इस स्पर्धा में भारत को दो दशक बाद पदक दिलाया। यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि पैरा स्पोर्ट्स में भारत की तैयारी लगातार मजबूत हो रही है।

एथलेटिक्स में कई उपलब्धियां, लेकिन गोल्ड कम – एथलेटिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा 16 पदक जीते, लेकिन इनमें सिर्फ तीन स्वर्ण रहे। गुलवीर सिंह ने एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में दो पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गुलवीर सिंह ने 10 हजार मीटर में रजत और पांच हजार मीटर में कांस्य पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंक में रजत जीतकर अपने कॉमनवेल्थ गेम्स करियर का दूसरा पदक हासिल किया।

पांच खेलों ने बढ़ाई सबसे ज्यादा चिंता – भारत की सबसे बड़ी चिंता उन खेलों को लेकर है, जिनमें एक भी पदक नहीं आया। यह इसलिए भी खासा चिंताजनक है, क्योंकि इनमें से कई खेल ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं और भारत पिछले कुछ वर्षों से इन पर लगातार निवेश कर रहा है।

स्विमिंग – 10 तैराकों की टीम होने के बावजूद भारत का खाता नहीं खुल सका। यह वही खेल है जिसमें विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा पदक दांव पर होते हैं। भारत के लिए यह अब भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स – आठ खिलाड़ियों का दल उतरा, लेकिन कोई भी पदक नहीं जीत सका। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिम्नास्टिक्स में बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर पर काफी काम किया है, लेकिन उसका असर पदकों में नहीं दिखा।

ट्रैक साइक्लिंग – सात खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन पदक नहीं मिला। ट्रैक साइक्लिंग में भारत लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है, जबकि कई देशों ने इसे अपनी पदक रणनीति का अहम हिस्सा बना लिया है।

लॉन बाउल्स – बर्मिंघम 2022 में महिलाओं की फोर टीम ने ऐतिहासिक स्वर्ण जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार छह खिलाड़ियों का दल गया, लेकिन कोई भी उस सफलता को दोहरा नहीं पाया।

'लोकतंत्र का असली मतलब है कि सत्ता हिलाई जा सकती है'

(तवलीन सिंह)

लोकतंत्र एक ऐसा पौधा है, जो जिंदा तब तक रहता है, जब तक आम नागरिक उसकी अहमियत समझते हों। इसलिए पिछले सप्ताह मुझे पहली बार लगने लगा कि भारत में लोकतंत्र को खतरा होने लगा है। ऐसा खतरा, जो छिप-छिपकर वार कर रहा है।

कहने को तो सब ठीक है। चुनाव होते रहते हैं, किसी न किसी राज्य में हर साल। ऊपर से काकरोच जनता पार्टी ने सबको याद दिलाया है कि लोकतंत्र का मतलब और उसका महत्त्व वे बच्चे भी समझ गए हैं, जिन्होंने शायद कभी किसी चुनाव में वोट नहीं डाला है।

जंतर-मंतर पर उन्होंने दिखाया है कि लोकतंत्र का असली मतलब है कि सत्ता हिलाई जा सकती है, जब आम लोगों को एहसास होने लगता है कि उनकी निजी शक्ति सत्ताधारियों से कहीं ज्यादा है। सो उस प्रधानमंत्री को उन्होंने घुटनों पर लाकर दिखाया, जो अपने बारे में बहुत बार कह चुके हैं कि उनकी छाती छप्पन इंच की है और उनके सामने दुनिया के बाकी नेता बौने लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी दिखाया है कि उनके सामने इस देश के बाकी नेता इतने ज्यादा बौने हैं कि उनके राजनीतिक दल आसानी से तोड़े जा सकते हैं।

जंतर मंतर पर युवाओं ने अपनी शक्ति दिखाई – तकरीबन सारे विपक्षी दल टूटकर बिखर चुके हैं, इतनी बुरी तरह कि चुनाव मैदान में मोदी के सामने कोई ताकतवर प्रतिद्वंद्वी दिखता ही नहीं है। युवाओं ने जंतर-मंतर से अपनी शक्ति न दिखाई होती, तो उनके भक्त आज भी पूरे यकीन से कहते फिरते कि 2029 में 'आएगा तो मोदी ही'।अब लगता है कि मोदी की टीम थोड़ी घबरा गई है। सोशल मीडिया पर जो होने लगा है, उसकी तरफ ध्यान देंगे तो देखेंगे कि मोदी सरकार और उनके समर्थकों ने एक ऐसी मुहिम छेड़ रखी है, जिसका मकसद काकरोच जनता पार्टी को बदनाम करना है।यह मैं इसलिए कह रही हूं कि सोशल मीडिया पर मेरी नजर दिन भर रहती है और वहां से जो आम लोगों की आवाज उठती है, उसे मैं पूरे ध्यान से सुनती हूं।जब से काकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया है, तब से मोदी के खास भक्त ऊंची आवाज में कहने लगे हैं कि जो हुआ वह अलोकतांत्रिक था और ऐसा किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश में हो ही नहीं सकता। यानी भारत ही एक ऐसा देश है, जहां युवाओं को प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टी-सीधी बातें बोलने के बावजूद उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

जंतर-मंतर पर उन्होंने दिखाया है कि लोकतंत्र का असली मतलब है कि सत्ता हिलाई जा सकती है, जब आम लोगों को एहसास होने लगता है कि उनकी निजी शक्ति सत्ताधारियों से कहीं ज्यादा है। सो उस प्रधानमंत्री को उन्होंने घुटनों पर लाकर दिखाया, जो अपने बारे में बहुत बार कह चुके हैं कि उनकी छाती छप्पन इंच की है और उनके सामने दुनिया के बाकी नेता बौने लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी दिखाया है कि उनके सामने इस देश के बाकी नेता इतने ज्यादा बौने हैं कि उनके राजनीतिक दल आसानी से तोड़े जा सकते हैं।

हुआ ऐसा कि मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें अरुंधति राय को जंतर-मंतर पर दिखाया गया है। वहां वे कहती हैं कि बहुत दिनों बाद उन्हें भारतीय होने पर गर्व होने लगा है।आगे यह मशहूर लेखिका कहती हैं कि अब वे खुशी से मर सकेंगी, क्योंकि देश के नौजवानों ने ऐसा कुछ करके दिखाया है, जिससे उनके दिल में एक बार फिर उम्मीद जाग गई है।

इस वीडियो को एक मोदी समर्थक ने 'एक्स' पर साझा करते हुए लिखा कि ऐसी बातें किसी और देश में लोग कह नहीं सकते। क्या चीन, उत्तर कोरिया या रूस में इस तरह की बातें कोई कर सकता है?

मैंने इस पोस्ट पर 'एक्स' में टिप्पणी की कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए उसकी तुलना तानाशाही देशों से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक देशों से करनी चाहिए।यहां याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप अमेरिकी टीवी चैनलों से थोड़े-बहुत भी परिचित हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां मशहूर एंकर किस तरह रोज डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं। कभी उनकी नकल करके, कभी उनकी नीतियों की आलोचना करके और कभी उनके परिवार की कथित भ्रष्ट आदतों पर टिप्पणी करके।

हैरानी तब हुई, जब मेरी इस टिप्पणी के बाद मुझे कितनी गालियां पड़ीं। कुछ लोगों ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई है, उसका वीजा रद्द कर उसे सीधे वापस भेज दिया जाता है।

सच यह है कि किसी विदेशी व्यक्ति ने अपने मेजबान देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर जंतर-मंतर पर खड़े होकर आवाज उठाई होती, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता था। मगर अरुंधति भारतीय हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।

मेरी इस बात से सोशल मीडिया पर ऐसी बहस छिड़ गई, जिसमें मुझे भी राष्ट्रविरोधी घोषित कर दिया गया और ढेर सारी गालियां सुनने को मिलीं, भाजपाइयों से भी और आम लोगों से भी।

कुछ लोगों ने कंगना रनौत की तरह यहां तक कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को कई लोग भगवान मानते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कुछ कहना न सिर्फ गलत है, बल्कि भगवान का अपमान भी है। इन बातों को सुनने के बाद मैं कुछ देर सोच में पड़ गई, क्योंकि मैंने इंदिरा गांधी का आपातकाल भी देखा है। तब भी हम लोग चुपके से इंदिरा गांधी को खूब गालियां दिया करते थे। और जब 1977 का चुनाव आया, तो मतदाताओं ने इंदिरा गांधी और उनके बेटे को उनके अपने चुनाव क्षेत्रों में हराकर दिखा दिया कि जनता की शक्ति कितनी बड़ी होती है। मोदी के दौर में, जब तक काकरोच जनता पार्टी नहीं बनी थी, किसी ने खुलकर बोलने की अगर हिम्मत नहीं दिखाई, तो उसकी वजह यह थी कि माहौल में खौफ बढ़ता जा रहा था। यहां तक कि जाने-माने टीवी एंकर भी अपनी बातें दबी जुबान में रखते हैं।

रही मेरी अपनी बात, तो मैं बेझिझक कहने को तैयार हूं कि मैं खुद फूंक-फूंककर चलती हूं और डर-डरकर अपने लेख लिखती हूं। ऐसा उन देशों में नहीं होता, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। भारत में ये जड़ें इतनी कमजोर हैं कि आम लोग भी मानते हैं कि लोकतंत्र की सीमा चुनाव जीतने तक ही रहती है। लोकतंत्र के लिए यह खतरनाक नहीं है क्या? (यह लेखिका के अपने विचार है)

कलेक्टर की सख्त चेतावनी: प्रसव के दौरान एक भी मातृ या शिशु मृत्यु हुई तो होगी जांच, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में अप्रैल से जुलाई तक संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की ब्लॉकवार समीक्षा की गई। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल, ऋचा सिंह, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, डीपीएम सहित दोनों विभागों के अधिकारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे।

मातृ और शिशु मृत्यु पर सख्त रुख

बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जिले में प्रसव के दौरान एक भी मातृ या शिशु मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में मृत्यु होती है तो उसकी जांच की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफकार्रवाई होगी। उन्होंने दोनों विभागों को आपसी समन्वय के साथ संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को प्रसव के दौरान होने वाली संभावित समस्याओं जैसे अधिक रक्तस्राव, खून की कमी, सामान्य या ऑपरेशन से प्रसव जैसी स्थितियों के बारे में पहले से जानकारी दी जाए। साथ ही प्रसव पीड़ा शुरू होने या गर्भावस्था पूरी होने पर उन्हें समय पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाए।

कुपोषण और टीबी उन्मूलन पर जोर

बैठक में पोषण पुनर्वास केंद्र की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने तथा आवश्यक दवा और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। टीबी और कुष्ठ रोग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मरीजों को नियमित दवा लेने, मास्क का उपयोग करने और संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि जिले में 8 बच्चों में कुष्ठ रोग के लक्षण पाए गए हैं और इस बीमारी के लक्षण विकसित होने में 3 से 5 वर्ष तक का समय लग सकता है।

एचपीवी वैक्सीन और योजनाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने 15 वर्ष की बालिकाओं और इच्छुक महिलाओं को एचपीवी वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि अब तक 1,883 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि 126 आवेदन सत्यापन और स्वीकृति के लिए लंबित हैं। उन्होंने इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।बैठक के अंत में कलेक्टर ने दोनों विभागों को स्कूलों और बच्चों से संबंधित जानकारी आपस में साझा करने तथा टीबी और कुष्ठ मुक्त जिला बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बेरला कला में प्रस्तावित खाद फैक्ट्री का विरोध, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के ग्राम बेरला कला में निर्माणाधीन/प्रस्तावित ग्लोबल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नामक खाद-दवा फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने बीते गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फैक्ट्री पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री बिना वैध पंजीयन के स्थापित की जा रही है, जिससे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि मामले में प्राथमिक सहयोग के लिए उन्होंने क्रांतिसेना से संपर्क किया था। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों के साथ जेसीपी शहर अध्यक्ष सूर्या सिंह चौहान सहित प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुलाकात कर ग्रामीणों की आपत्तियों से अवगत कराया। ग्रामीणों के अनुसार, उद्योग विभाग से जानकारी लेने पर अधिकारियों ने बताया कि 'ग्लोबल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड' उद्योग विभाग में पंजीकृत नहीं है। इस जानकारी के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बिना पंजीयन संचालित या प्रस्तावित फैक्ट्री पर तत्काल रोक लगाने, पर्यावरण एवं जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि फैक्ट्री स्थापित होती है तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा और आसपास के जल स्रोतों के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

क्रांतिसेना और जेसीपी के प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीणों के हित और पर्यावरण संरक्षण के लिए वे कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे।

शासकीय हाई स्कूल नदीगांव में छात्राओं को मिली निःशुल्क साइकिल, सरस्वती साइकिल योजना के तहत किया गया वितरण..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बरमकेला विकासखंड अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल नदीगांव में सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई।कार्यक्रम में डोली पाव, रोशनी निषाद और अरुणा पाव को साइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच गौरीशंकर विश्वाल रहे।सरपंच गौरीशंकर विश्वाल ने छात्राओं को बधाई देते हुए नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शासन की यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए काफी लाभदायक है, जिससे उनकी शिक्षा में आने वाली दूरी की बाधा कम होगी।इस अवसर पर शाला विकास समिति अध्यक्ष विकास विश्वाल, उपाध्यक्ष एवं लिसी सरपंच सन्यासी सिदार, पंचायत सचिव तोषराम पटेल, प्राचार्य धजाराम जयपुरी, शिक्षक खीरसागर पटेल, बनमाली बरिहा, सुरेंद्र कुमार सोनवानी, निरुपमा पाणिग्राही, अर्चना नगेशिया, संकुल समन्वयक प्रशांत शराप तथा पालक फागुलाल पाव, धनीराम निषाद, संतराम पाव और यशोदा आदित्य सहित विद्यालय परिवार एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने कहा कि इस तरह की योजनाएं छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

दो साल से प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त के लिए भटक रही हितग्राही, कई आवेदन के बाद भी नहीं मिला न्याय, प्रशासनिक उदासीनता पर उठे सवाल..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन जिले में एक हितग्राही पिछले करीब दो वर्षों से अपनी पहली किस्त के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। मामला सरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरसी का है, जहां प्रशासनिक लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

2023-24 में आवास स्वीकृत, लेकिन पहली किस्त नहीं मिली-ग्राम पंचायत सुरसी की निवासी विशाखा साहू, पिता गौतम साहू के नाम वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। हितग्राही का कहना है कि स्वीकृति मिलने के बाद भी उन्हें पहली किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई। जब उन्होंने जनपद पंचायत कार्यालय में जानकारी ली तो पता चला कि पहली किस्त की राशि किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित हो गई है।

कई बार आवेदन, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई-विशाखा साहू ने इस संबंध में 5 दिसंबर 2024 को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को लिखित आवेदन देकर जांच और राशि दिलाने की मांग की थी। इसके बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ा। पीड़िता का कहना है कि उसने जनपद पंचायत सीईओ, जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर जनदर्शन में भी कई बार आवेदन दिए, लेकिन आज तक न तो जांच पूरी हुई और न ही उन्हें उनकी पहली किस्त मिल सकी।

कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हितग्राही-पीड़िता का आरोप है कि हर बार अधिकारियों से केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अपनी ही स्वीकृत योजना का लाभ पाने के लिए उसे बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होने के कारण पक्का मकान बनाने का सपना अधूरा रह गया है।

प्रशासनिक लापरवाही पर उठ रहे सवाल-यह मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि किसी हितग्राही की राशि दूसरे के खाते में चली गई है, तो उसकी जिम्मेदारी तय कर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर एक गरीब हितग्राही को अपने ही अधिकार के लिए वर्षों तक भटकने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है?

निष्पक्ष जांच और राशि दिलाने की मांग-ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा विशाखा साहू को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों का समाधान नहीं किया गया तो आम लोगों का सरकारी योजनाओं और प्रशासन पर भरोसा कमजोर होता जाएगा।

छत्तीसगढ़ में नई तकनीक व कौशल विकास का नया अध्याय, 500 करोड़ रुपये से बदलेगी राज्य की डिजिटल तस्वीर: भाजपा

भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हार्दिक आभार माना

*गरियाबंद (प्रेरणाश्रोत)।:- * भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन' को दी गई ऐतिहासिक मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति देने वाला एक दूरदर्शी निर्णय बताया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के डिजिटल रोडमैप को धरातल पर उतारने के नाम पर केवल जुबानी जमाखर्च किया जबकि भाजपा की साय सरकार का वास्तविक धरातल पर काम नजर आ रहा है।भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का यह मिशन 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये की राशि

खर्च की जाएगी। यह मिशन न केवल बड़े शहरों तक सीमित रहेगा, बल्कि इसका मुख्य फोकस राज्य के दूर-दराज के जिलों, छोटे शहरों और कस्बों तक एआई की पहुँच सुनिश्चित करना है, ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचे। इस योजना के मुख्य बिन्दुओं की चर्चा करते हुए श्री चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन के तहत राज्यभर में अत्याधुनिक 100 एआई डेटा लैब का निर्माण किया जाएगा।

शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। युवाओं के नवाचार को बल देने के लिए 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के 6 लाख विद्यार्थियों तथा 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासकीय कामकाज को सुगम, पारदर्शी और तीव्र बनाने के लिए 50 से अधिक एआई-आधारित सेवाओं का विकास होगा।भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग हमेशा यह राग अलापते रहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पूरे देश को कम्प्यूटरीकृत करने का सपना देखा था। लेकिन सच्चाई यह है कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी सरकारों ने उनके सपनों को धरातल पर साकार करने की जरा भी पहल नहीं की। कांग्रेस ने तकनीक के नाम पर केवल बातें कीं, जबकि भाजपा की साय सरकार ने नीतियों को ज़मीन पर उतारकर यह साबित कर दिखाया है कि सुशासन और डिजिटल परिवर्तन कैसे लाया जाता है! श्री चंद्राकर ने कहा कि यह मिशन भारत सरकार के 'इण्डिया एआई मिशन' के अनुरूप छत्तीसगढ़ को एक उत्तरदायी, नवाचार-आधारित और भविष्य-उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

दिवसीय एयरोमॉडलिंग प्रशिक्षण संपन्न, विद्यार्थियों ने सीखे विमान निर्माण और उड़ान के वैज्ञानिक सिद्धांत

जशपुर नगर। कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जिले के विद्यार्थियों के लिए संकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर में आयोजित 5 दिवसीय आवासीय एयरोमॉडलिंग प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच एवं नवाचार के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से कराए गए इस प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को विमानन विज्ञान, एयरोडायनामिक्स एवं एयरोमॉडलिंग के सिद्धांतों को व्यवहारिक गतिविधियों के साथ सीखने का अवसर मिला। संयुक्त कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा एवं जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिन्हा के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 40 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। पाँच दिनों तक विद्यार्थियों ने विमान उड़ान के वैज्ञानिक सिद्धांत, विमान की संरचना, उड़ान नियंत्रण प्रणाली, एयरफॉइल, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, सेंटर ऑफ ग्रैविटी तथा आधुनिक विमानन

तकनीकों का अध्ययन किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 3ष्ठ वर्चुअल रियलिटी तकनीक के माध्यम से कॉकपिट एवं विमान संचालन का आभासी अनुभव भी कराया गया। प्रशिक्षक सुभाष देवांगन और राजेश राजपूत ने विद्यार्थियों को वायुगतिकी की ट्रेनिंग दी। एयरोमॉडल प्रशिक्षण के प्रायोगिक सत्रों में विद्यार्थियों ने पेपर प्लेन, बूमरैंग, एयरक्राफ्ट पज़ल्स तथा एयरोमॉडल निर्माण जैसी गतिविधियों में भाग लिया। अंतिम चरण में उन्होंने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में एयरोमॉडल के संतुलन, नियंत्रण और उड़ान परीक्षण की प्रक्रिया को समझा। यशस्वी जशपुर के नोडल अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण विद्यार्थियों को केवल विज्ञान की सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं देते, बल्कि उन्हें व्यावहारिक प्रयोग, समस्या समाधान, टीमवर्क और नवाचार आधारित सोच विकसित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन में यशस्वी जशपुर के अवनीश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हर माह अंतिम मंगलवार को मुख्यमंत्री करेंगे राज्यस्तरीय समीक्षा, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

सुशासन की नई पहल: पारस पोर्टल से होगी योजनाओं की रियल टाइम निगरानी

सीएम हेल्पलाइन, एग्रीस्टैक, सेवा सेतु, मोबाइल टॉवर और स्कूल शिक्षा सहित छह प्रमुख एजेंडों की समीक्षा

बलरामपुर /मूक पत्रिका

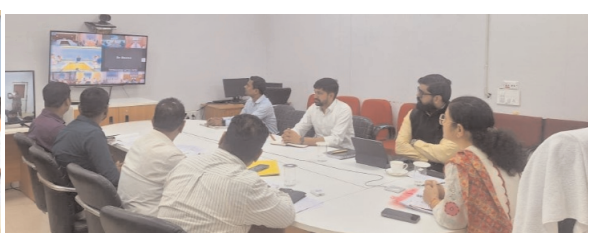

दुर्गेश गुप्ता,-बलरामपुर। प्रदेश में सुशासन को नई दिशा देते हुए राज्य सरकार ने पारस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रमुख शासकीय योजनाओं और जनसेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू कर दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में पारस पोर्टल की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य की प्रमुख योजनाओं और सेवाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी, जिससे योजनाओं का लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।मुख्यमंत्री ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े छह प्रमुख विषयों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को तय समय-सीमा में परिणाम देने और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

सीमांकन में देरी पर जताई कड़ी नाराजगी-राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सीमांकन के लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी समय पर सीमांकन नहीं होना आम नागरिकों के साथ अन्याय है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सीमांकन प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

एग्रीस्टैक में 100 प्रतिशत किसान पंजीयन के निर्देश-मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीस्टैक केवल धान खरीदी तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का आधार है। उन्होंने सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी पात्र किसान के वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी।

सीएम हेल्पलाइन को बनाया जाए प्रभावी समाधान मंच-मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 का उद्देश्य आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। उन्होंने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर दिया। बैठक में बताया गया कि हेल्पलाइन में अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है तथा 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर संतुष्टि जताई है।

सेवा सेतु से सभी सेवाएं हों ऑनलाइन-मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में 27 विभागों की 721 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने शेष सेवाओं को भी जल्द ऑनलाइन करने तथा ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा सेतु का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

ग्रामीण विकास, मोबाइल कनेक्टिविटी और शिक्षा पर विशेष फोकस-मुख्यमंत्री ने विकसित भारत जी-रामजी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टावरों की स्थापना में तेजी लाने पर बल दिया, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच सके।स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सभी स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने, सहजन, कटहल सहित उपयोगी पौधों का रोपण करने तथा बच्चों में पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।

बलरामपुर से जुड़े अधिकारी भी रहे शामिल-बैठक में बलरामपुर जिले से कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी सहित संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

मुख्य बिंदु-

* पारस पोर्टल से योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग।
* हर माह अंतिम मंगलवार को राज्यस्तरीय समीक्षा।
* सीमांकन मामलों में देरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।
* एग्रीस्टैक में सभी पात्र किसानों का 100 प्रतिशत पंजीयन।
* सीएम हेल्पलाइन, सेवा सेतु और स्कूल शिक्षा योजनाओं की समीक्षा।
* दूरस्थ क्षेत्रों में 476 मोबाइल टावरों की स्थापना में तेजी।

पारस पोर्टल से योजनाओं की होगी नियमित समीक्षा, मुख्यमंत्री ने समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

हर माह अंतिम मंगलवार को होगी राज्यस्तरीय समीक्षा

बीजापुर/मूक पत्रिका

राज्य सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी को और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन से पारस पोर्टल के माध्यम से पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन-1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी योजना, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना और स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने सीमांकन प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण, एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन, सेवा सेतु के माध्यम से अधिक से अधिक शासकीय सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने तथा जनशिकायतों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया।मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इससे योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी होगी और आवश्यक सुधारात्मक कदम समय पर उठाए जा सकेंगे। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी. दयानंद एवं राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप भी बैठक में शामिल हुए और जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा प्रक्रिया में भागीदारी की।

युवा नेतृत्व को मिला सम्मान,संगठन ने आकाश शर्मा को सौंपा रायगढ़ जिले का प्रभार

रायगढ़/मूक पत्रिका

=भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने अपनी सांगठनिक जड़ों को और अधिक मजबूत ऊर्जावान और गतिशील बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है युवाओं के चहेते संघर्षशील और जमीनी स्तर पर निरंतर सक्रिय रहने वाले प्रखर युवा नेता आकाश शर्मा को संगठन ने भाजयुमो के रायगढ़ जिला सह प्रभारी की बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है आकाश शर्मा की यह नियुक्ति केवल एक पद की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनकी सालों की निष्ठा, कठिन परिश्रम और युवाओं को एकजुट करने की अद्वितीय क्षमता का सम्मान है। वे लंबे समय से धरातल पर रहकर युवाओं की आवाज बनते रहे हैं और हर मोड़ पर संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी लगन के साथ कार्य करते आ रहे हैं।आकाश शर्मा की सबसे बड़ी ताकत युवाओं के बीच उनका सहज जुड़ाव और मजबूत संवाद क्षमता है। चाहे संगठन के अभियानों को जन-जन तक पहुंचाना हो या फिर युवाओं में राष्ट्रवाद और सेवा भाव का अलख जगाना हो, उन्होंने हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया है। संगठन में उनकी इसी निरंतर सक्रियता, रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने उन पर यह बड़ा विश्वास जताया है।

नया लक्ष्य : रायगढ़ के कोने-कोने तक पहुंचेगा भाजयुमो का परचम

इस नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ आकाश शर्मा रायगढ़ जिलेभर में भाजयुमो के अभियानों को एक नई धार देंगे। उनका मुख्य उद्देश्य जिले के हर मंडल और बूथ स्तर तक पहुंचकर प्रतिभावान और ऊर्जावान युवाओं को भाजयुमो की विचारधारा से जोड़ना है। आकाश शर्मा ने कहा किज्÷संगठन ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है, मैं उस पर पूरी तरह खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यह जिम्मेदारी मेरी अकेली नहीं, बल्कि रायगढ़ के हर उस युवा कार्यकर्ता की है जो राष्ट्र निर्माण और जनसेवा के लिए समर्पित है। हमारा संकल्प रायगढ़ जिले के कोने-कोने तक भाजयुमो का संदेश पहुंचाना और युवाओं की ताकत को एकजुट कर संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है

स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, बिना सीढ़ी बच्चों को छत पर चढ़ाकर कराई टंकी की जांच

फिंगेश्वर।। फिंगेश्वर ब्लॉक में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया हैं। फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम कोसमखुंटा मिडिल स्कूल में पानी की टंकी में पानी चेक कराने के लिए स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डाल दी गई। बच्चों को बिना सीढ़ी के दीवार के सहारे स्कूल की छत पर चढ़ाया गया, जबकि छत के बिल्कुल पास से हाई टेंशन बिजली गुजर रही हैं। जरा-सी चुक किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी। यहां यह बताना लाजमी है कि बच्चें छत पर चढ़े हैं, छत में कोई बाउंड्रीवाल नहीं हैं। कभी भी कोई बच्चा नीचे गिर सकता था हैरानी की बात है कि शासकीय मिडिल स्कूल कोसमखुंटा के प्रधान पाठक सुशील दीवान पानी की टंकी देखने के लिए बच्चों को ही छत पर भेज दिया। बच्चों ने बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था और बिना सीढ़ी के दीवार के सहारें छत पर चढ़कर टंकी की जांच की जब प्रधान पाठक से इस लापरवाही के बारे में पूछा तो कहा कि गलती तो हुई हैं, पानी की टंकी को देखने के लिए बच्चों को ही छत पर भेजा था। हैरानी की बात यह है कि स्कूल की छत से कुछ ऊपर से हाई टेंशन बिजली की लाईन गुजर रही हैं। ऐसे मे थोड़ी-सी लापरवाही भी बच्चों के जान पर भारी पड़ सकती थी। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी हेमंत कुमार साहू ने बड़ी लापरवाही मानते तत्काल कार्यवाही करने की बात कही हैं। अब सवाल यह है कि बच्चों से ऐसे जोखिम भरा काम क्यों कराया गया ? यदि कोई हादसा हो जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता ? फिलहाल इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

आजादी के 77 साल बाद भी 'अंतिम विदाई' को तरसता फर्सवानी, खुले आसमान के नीचे सुलगती चिताएं

तालाब की मेढ़ पर भीगते शव देख छलका ग्रामीणों का दर्द

सारंगढ़/मूक पत्रिका

क्या आजादी के सात दशकों बाद भी एक इंसान को मरकर सुकून से पंचतत्व में विलीन होने का हक नहीं है? क्या विकास के खोखले नारों की हकीकत यही है कि अपनों के जाने के गम में डूबे परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सिर छिपाने की जगह भी न मिले फर्सवानी गांव से आती तस्वीरें किसी का भी कलेजा कपा देने के लिए काफी हैं, जहां आज भी बारिश के थपेड़ों के बीच, पन्नियों और तिरपाल की आड़ में अपनों की चिताओं को मुखाग्नि दी जा रही है।

अंधे-बहरे सिस्टम के खिलाफ भडक़ा जनाक्रोश-ग्रामीणों ने वर्षों तक गुहार लगाई, अर्जियां दीं, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब फर्सवानी का सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है। गांव की गलियों में दुख से ज्यादा गुस्सा तैर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पंचायत और प्रशासन ने अपनी नींद से जागकर तत्काल सर्वसुविधायुक्त मुक्तिधाम का निर्माण शुरू नहीं कराया, तो वे सडक़ों पर उतरने से नहीं हिचकेंगे

कलेक्टोरेट कूच या घर-घर से चंदा-खुद संवारेंगे अपनों का अंतिम सफर, लाचार और आक्रोशित ग्रामीणों ने अब सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टोरेट जाने का की तैयारी में हैं, ताकि अफसरशाही को उनकी नाकामी का अहसास कराया जा सके। वहीं, ग्रामीणों ने यह भी कसम खाई है कि अगर शासन-प्रशासन इतना लाचार और बेबस हो चुका है कि वह मुक्तिधाम भी नहीं बना सकता, तो वे खुद घर-घर जाकर झोली फैलाएंगे, एक-एक रुपया चंदा जुटाएंगे और अपनों की गरिमा की खातिर खुद मुक्तिधाम बनाएंगे। लेकिन अब इस अनदेखी और बेअदबी को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!

भीगती चिताएं, टूटती सांसें-जिस गांव में जिंदगी भर इंसान ने हाड़-तोड़ मेहनत की, वहां मौत के बाद उसे दो गज जमीन पर एक छत नसीब नहीं है। कहने को मुख्य बस्ती से 2 किलोमीटर दूर एक मुक्तिधाम का ढांचा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन दुर्गम रास्ते और बेतुकी दूरी के कारण वहां तक शव ले जाना अपने आप में किसी सजाये-मौत से कम नहीं। लाचार होकर ग्रामीण आज भी गांव के तालाब की मेढ़ पर अपनों का दाह-संस्कार करने को मजबूर हैं। सोचिए, उस परिवार पर क्या बीतती होगी, जब अपनों को खोने के आंसू अभी सूखे भी नहीं होते और बारिश की बूंदें जलती चिता को बुझाने लगती हैं! यह सिर्फ एक शव का भीगना नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासन और पंचायत व्यवस्था का पूरी तरह से बह जाना है।

जगदलपुर में चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाला बदमाश गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई

जगदलपुर /मूक पत्रिका

बस्तर जिले के जगदलपुर में आम लोगों को धारदार चाकू दिखाकर डराने-धमकाने वाले एक युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, वीर सावरकर भवन स्थित स्केटिंग मैदान के पास एक युवक हाथ में बटनदार चाकू लहराकर राहगीरों को भयभीत कर रहा था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान राकेश मंडावी (21 वर्ष), निवासी शांति नगर, दुर्गा मंदिर के पास, थाना बोधघाट, जिला बस्तर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक धारदार बटनदार चाकू बरामद कर जब्त किया गया।पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विधिवत गिरफ्तारी की कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में की गई। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जिले में असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर के नेतृत्व में किया गया। कार्रवाई में उपनिरीक्षक अरुण मरकाम, क्क्स्ढ्ढ भूपेंद्र पैकरा, प्रधान आरक्षक मोहन कश्यप तथा आरक्षक वरुण ठाकुर, हरीश, तोमन बघेल, बलराम, भीम एवं तामेश्वर चंद्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भैरमगढ़ को 1.52 करोड़ की सौगात, 11 विकास कार्यों को मंजूरी, 6 सीसी सड़कें और 5 आरसीसी नालियां बनेंगी, वार्डों में सुधरेंगी बुनियादी सुविधाएं

बीजापुर/मूक पत्रिका

भैरमगढ़ नगर पंचायत में सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ 52 लाख 14 हजार रुपए के 11 विकास कार्यों को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्वीकृति आदेश जारी कर दिए हैं। स्वीकृत कार्यों में छह सीसी सड़कें और पांच आरसीसी नालियों का निर्माण शामिल है।विभाग के अनुसार, 1 करोड़ 12 लाख 75 हजार रुपए की लागत से छह सीसी सड़कें बनाई जाएंगी। इनमें वार्ड क्रमांक-3 में बेलतीपदर रोड से आंगनबाड़ी केंद्र तक तथा वार्ड क्रमांक-14 में बाजार स्थल से पुसनार पहुंच मार्ग का निर्माण प्रमुख है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक-2, 11, 12 और 13 में भी सीसी सड़कें बनाई जाएंगी।नगर पंचायत क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था बेहतर करने के लिए 39 लाख 39 हजार रुपए की लागत से पांच आरसीसी नालियों का निर्माण भी स्वीकृत किया गया है। इसके तहत वार्ड क्रमांक-8 और 13 में एक-एक तथा वार्ड क्रमांक-15 में दो नालियों का निर्माण होगा। इन विकास कार्यों के पूरा होने से नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में आवागमन सुगम होने के साथ ही बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

स्थानांतरण नौकरी का हिस्सा, नई जगह कुछ न कुछ जरूर सीखता : एसपी बेमेतरा त्रिलोक बंसल

डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा को गरिमामयी समारोह में दी गई विदाई एवं किया गया सम्मान

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बेमेतरा पुलिस जिले में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बेमेतरा राजेश कुमार झा का स्थानांतरण राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया। उन्हें पुलिस कार्यालय बेमेतरा के सभा कक्ष में गरिमामयी विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन कर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके, रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक सोनल ग्वाला, सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, रीडर-1निरीक्षक कृष्णकांत सिंह ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया एवं उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। साथ ही उनके स्वस्थ, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना की गई। स्थानांतरित उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बेमेतरा राजेश कुमार झा का जिले में लगभग 05 साल का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अनेक गंभीर मामलों में उनके पर्यवेक्षण से उल्लेखनीय सफलता मिली।

उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बेमेतरा राजेश कुमार झा ने बेमेतरा जिले में बिताए अपने अनुभव को उपस्थित स्टाफ के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवाकाल के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों एवं अधीनस्थ व साथी अधिकारियों/कर्मचारियों का उन्हें पूरा सहयोग मिला। जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसे उन्होंने पूरी लगन व ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया।

एसपी बेमेतरा त्रिलोक बंसल ने उनके कार्यों की प्रशंसा एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि स्थानांतरण नौकरी का हिस्सा होता है। अधिकारी या कर्मचारी जहां कहीं भी जाता है, वहां से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। उन्होंने कहा कि काम करने में आनंद तभी आता है, जब जनता का सहयोग मिलता है। राजेश कुमार झा ने अच्छे कार्यों से जनता का विश्वास जीता। उन्होंने अपराधों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निराकरण का सार्थक प्रयास किया। उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बेमेतरा राजेश कुमार झा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई।

एएसपी डॉ. हरीश यादव ने कहा कि डीएसपी राजेश कुमार झा ने अपने सेवा काल के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेश कुमार झा डीएसपी (मुख्यालय) के तौर पर पदस्थ रहते हुए अपने लगभग 05 वर्षों के कार्यकाल में अच्छा काम किया। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे नई जिम्मेदारी भी सफलता के साथ निभाएंगे। उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने एवं नई जिम्मेदारियों में सफलता पाने के लिए शुभकामनाएँ दी।

*एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का एवं डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके ने उनके सेवा काल व चुनाव के समय निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएँ दी।

*रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, निरीक्षक सोनल ग्वाला, मयंक मिश्रा, कृष्णकांत सिंह एवं पुलिस कार्यालय स्टाफ ने भी उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बेमेतरा राजेश कुमार झा के कार्यों की सराहना करते हुए अपने अनुभव साझा किए एवं नई जगह के लिए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।

इस विदाई समारोह में पुलिस अधीक्षक बेमेतरा त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके, रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक सोनल ग्वाला, सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, रीडर-1निरीक्षक कृष्णकांत सिंह, स्टेनो संतोष सोनवानी, मुख्यलिपिक उप निरीक्षक (अ) हरिओम विश्वकर्मा, उप निरीक्षक (अ) प्रदीप देशमुख, सउनि (अ) महेन्द्र भुआर्य, प्रवीण लोहले, दीपक गर्जेलवार,अजय देवांगन, सउनि विष्णु सप्रे, रीडर-2 प्रधान आरक्षक वर्षा चौबे प्रधान आरक्षक ताम्रध्वज देशमुख, ऐश्वर्य सिंह क्षत्री, खोमलाल साहू, आरक्षक अखिलेश क्षत्री, दीपक साहू, मनीष देवांगन, अमित यादव, जितेन्द्र नेताम, वासुदेव साहू, गेंदलाल चतुर्वेदी, योगेश्वर वर्मा, अमरदीप लहरे, राजेश नाथ योगी, भरत साहू, बिरेन्द्र चंद्राकर, गेल्विन साहू, धर्मेन्द्र राजपूत, सतीश साहू, अर्जुन चंद्राकर, कमलेश साहू, महिला आरक्षक भारती राजपूत, द्रोपती ठाकुर, संध्या विश्वकर्मा, प्रियंका सिंह, राही यादव, सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

कार्यक्रम का संचालन रीडर-2 प्रधान आरक्षक वर्षा चौबे ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का ने किया।

स्वतंत्रता दिवस पर सैमसंग लेकर आया है 'द बिग बेस्पोक एआई फेस्ट', ढेरों ऑफर्स के साथ एआई अप्लायंसेज़ पर 19,470 रुपये तक कैशबैक

गुरुग्राम: सैमसंग इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी विशेष सेल 'द बिग बेस्पोक एआई फेस्ट' की घोषणा की है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत कंपनी अपने बेस्पोक एआई होम अप्लायंसेज़ पर आकर्षक ऑफर्स और कैशबैक दे रही है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक के जरिए रोजमर्रा के घरेलू कामों को आसान बनाकर उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और समय उपलब्ध कराना है। सैमसंग के एआई-संचालित रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वॉशर-ड्रायर कॉम्बो जैसे स्मार्ट होम अप्लायंसेज़ घरेलू कामों को आसान बनाने के साथ-साथ समय की बचत में भी मदद करते हैं। कंपनी का कहना है कि इन स्मार्ट सॉल्यूशंस की मदद से परिवार घर के कामों में कम समय देकर अपनों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। देश की आज़ादी के वर्ष 1947 को खास अंदाज में याद करते हुए कंपनी चुनिंदा बेस्पोक एआई अप्लायंसेज़ पर 19,470 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। इसके अलावा, सैमसंग केयर+ के तहत चुनिंदा रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर एक वर्ष की विस्तारित वारंटी के साथ दो वर्ष की अतिरिक्त वारंटी मुफ्त मिलेगी। वहीं, चुनिंदा सिंगल-डोर रेफ्रिजरेटर के लिए केवल 99 रुपये में एक वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प भी उपलब्ध है। खरीदारी को और आसान बनाने के लिए सैमसंग फाइनेंस+ के जरिए जीरो डाउन पेमेंट सहित लचीले फाइनेंस विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। 25 किलोग्राम वॉशर-ड्रायर कॉम्बो पर 20/5 फाइनेंस स्कीम के तहत '1 ईएमआई ऑफ' का विशेष लाभ भी मिलेगा। इस योजना में 20 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर पहली ईएमआई का भुगतान सैमसंग करेगा। विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में ईएमआई 890 रुपये प्रति माह से शुरू होगी।

रेंज रोवर SV अल्ट्रा : भारत में रेंज रोवर लक्ज़री का बेहतरीन उदाहरण/अंदाज़

मुंबई: रेंज रोवर ने रेंज रोवर SV अल्ट्रा को पेश किया है, जो रेंज रोवर की लक्ज़री और सर्वोच्च विशिष्टता है। उन्नत फिनिश को विश्व की पहली ऑडियो तकनीक के साथ जोड़ते हुए, SV अल्ट्रा अब तक बनाई गई सबसे लग्ज़रीयस और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत रेंज रोवर है। रेंज रोवर SV अल्ट्रा में इमर्सिव ऑडियो तकनीकों की शृंखला में अब क्रांतिकारी एसवी इलेक्ट्रोस्टेटिक साउंड भी शामिल है, जो केबिन को एक कॉन्सर्ट हॉल में बदल देती है, साथ ही बॉडी एंड सोल सीट्स (BASS) और सेंसरी हैप्टिक फ्लोर (Sensory Haptic Floor) भी उपलब्ध हैं। एसवी इलेक्ट्रोस्टेटिक साउंड किसी वाहन में इलेक्ट्रोस्टेटिक ऑडियो तकनीक का विश्व का पहला अनुप्रयोग है। इलेक्ट्रोस्टेटिक साउंड सिस्टम में हर सीट के लिए एक पर्सनल ऑडिटोरियम बनाने हेतु 21 लाइटवेट थिन-फिल्म ट्रांसड्यूसर लगे हैं। ये 21 इलेक्ट्रोस्टेटिक पैनल नए डिज़ाइन किए गए विंग्ड हेडरेस्ट्स, सीटबैक्स और मौजूदा स्पीकर लोकेशंस — जिनमें हेडलाइनिंग में लगे स्पीकर भी शामिल हैं — में इंटीग्रेट किए गए हैं, जो ऑडियो का निरंतर प्रवाह, एक सहज फ्रीक्वेंसी रेंज और सुसंगत, बिना किसी विकृति वाली ध्वनि स्पष्टता प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रोस्टेटिक स्पीकर्स को पांच मौजूदा बास लाउडस्पीकर्स के साथ-साथ बॉडी एंड सोल सीट्स का समर्थन प्राप्त है, जो बेजोड़ बास सपोर्ट देते हैं।

स्टैण्डर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड नतीजे दर्ज किए और बड़े रणनीतिक विस्तार की शुरुआत की

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख हाई-प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एसइटीएल) ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए एक और रिकॉर्ड-तोड़ तिमाही नतीजों की घोषणा की है। साथ ही, कंपनी ने दो अहम रणनीतिक कदम भी उठाए हैं जो कंपनी की विकास की दिशा को नई शक्ल देंगे।

एसइटीएल की कुल आय 252.2 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल के मुकाबले 41.5त्न ज़्यादा है। एबिटडा 44.1 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 27.3त्न की बढ़ोतरी हुई और मार्जिन 17.5त्न पर बना रहा। टैक्स से प्रॉफिट बिफ़ोर टैक्स 26.5त्न बढ़कर 36 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टैक्स के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.6त्न बढ़कर 26.7 करोड़ रुपये रहा, जिससे पैट मार्जिन 10.6त्न हो गया। खास बात यह है कि यह ग्रोथ तब हासिल हुई जब कंपनी अपने नए ग्रोथ प्लेटफ़ॉर्म में भारी निवेश कर रही थी। — यह कंपनी के मुख्य कारोबार की मज़बूती और कैश बनाने की क्षमता का संकेत है। एमडी नागेश्वर राव कंडुला ने इस तिमाही के नतीजों को किसी एक बार की कामयाबी के बजाय लगातार और दोहराए जा सकने वाले अच्छे प्रदर्शन का सबूत बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि एसइटीएल भारत का हाई-प्रिसिजन इंजीनियरिंग पावरहाउस बन रहा है। उन्होंने जीस्केल के निर्माण और जीएल हक्कों के साथ साझेदारी, दोनों में टीम के शानदार काम का श्रेय दिया। नेचुरल, स्पष्ट ऑडियो को डिटेल और प्रिसिज़न के साथ ट्रांसमिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रत्येक इलेक्ट्रोस्टेटिक स्पीकर मात्र 1mm मोटी एक अल्ट्रा-लाइट, अल्ट्रा-रिस्पॉन्सिव मेम्ब्रेन से युक्त है। यह मेम्ब्रेन दो पर्फोरेटेड मेटैलिक प्लेट्स के बीच स्थित होती है, जिन पर एक ऑडियो सिग्नल लागू किया जाता है, और यह पारंपरिक स्पीकर की तुलना में 1,000 गुना तेज़ी से रिस्पॉन्ड करती है।

ईरान के पास बातचीत का आखिरी मौका: डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को फिर दी धमकी

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत जल्द ही किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। यह कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हम होर्मुज को खोलने की बात कर रहे हैं। इसे सचमुच मंगलवार तक खोल दिया जाएगा। पूरी तरह से खोल दिया जाएगा।

ट्रंप ने आगे कहा कि यह पहला चरण है और दूसरे चरण में हम परमाणु मुद्दे पर बात करेंगे। इस मामले में हमारा रुख बहुत सख्त है। उनके (ईरान के) पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। बातचीत अभी भी चल रही है। यह उनके लिए आखिरी मौका है। एक अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करने का यह उनका अंतिम अवसर है।

ईरानी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को ट्रंप के 'अप्रत्यक्ष वार्ता' से जुड़े दावे

को सिरे से खारिज कर दिया। बाघेई ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, किसी प्रतिनिधि का स्वागत करने या फिर किसी को बातचीत के लिए भेजने की हमारी कोई योजना नहीं है। फिलहाल हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व के सामने दो विकल्प रखे कि समझौता करे या पूरी तरह आत्मसमर्पण। ट्रंप ने यह चेतावनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबे बयान के जरिये दी।

इस बयान में ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर 'दोहरा रवैया' अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ईरान पहले बातचीत के लिए 'गिड़गिड़ा रहा था'। लेकिन बाद में सार्वजनिक रूप से कह दिया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है।

ट्रंप ने लिखा, ईरान इसे माने या न माने। लेकिन हम वास्तव में उस समस्या के समाधान को लेकर बात कर रहे हैं, जिसे उसने दशकों से पैदा किया है।

ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के दावों को भी खारिज किया। यह समुद्री मार्ग दुनिया के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि ईरान यह कहता है कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण है, जबकि यह इलाका पहले से ही अमेरिकी नौसेना और उसकी 'नाकेबंदी' या 'स्टील की दीवार' के नियंत्रण में है।

ट्रंप ने कहा कि इस जलडमरूमध्य से आवाजाही पूरी तरह अमेरिका की इच्छा पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंचेगा, जब तक हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। और कुछ भी नहीं पहुंचेगा, जब तक कोई समझौता या पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं हो जाता।

ईरान में अब तक 50 जासूसी के आरोपियों को फांसी

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने इस्राइल के लिए जासूसी के आरोप में सोमवार को अपने दो और नागरिकों को फांसी दे दी। यह सजा ऐसे तनावपूर्ण समय में दी गई, जब ईरान पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ओमिद बेहजाद और पूरिया सफवत पर आरोप था कि उन्होंने पिछली गर्मियों में हुई छोटी लड़ाई और हालिया संघर्ष के दौरान इस्राइल को सैन्य और सुरक्षा ठिकानों की लोकेशन (कोऑर्डिनेट्स) के साथ-साथ तस्वीरें और जानकारी भेजी थीं। जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के बाद 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर फिर से हमले किए। इस्राइल की सैन्य रणनीति की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने मार्च में बताया था कि मौजूदा ईरान संघर्ष के दौरान इस्राइल ने मुखबिरों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के चेकपॉइंट्स को निशाना बनाया था।

'ह्यूमन राइट्स वॉच' की 24 जुलाई को

जारी रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पिछले चार महीनों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अस्पष्ट आरोपों में कम से कम 50 लोगों को फांसी दी है। इनमें कई 18 और 19 साल के युवा भी शामिल हैं। जेनेवा में ईरान के स्थायी मिशन ने इस संबंध में टिप्पणी के लिए अनुरोध का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि, तेहरान ने पहले भी कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों से इन्कार करता रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, ईरान ने रास्ता निर्धारित किया है, इस मार्ग के अलावा किसी भी अन्य समुद्री रास्ते से जहाजों को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, अमेरिका ने (इस्लामाबाद) समझौता ज्ञापन के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए ईरान की व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में समझौते का उल्लंघन किया। अमेरिका ने न केवल समझौता ज्ञापन का उल्लंघन किया बल्कि विवाद सुलझाने के लिए बने समाधान पैनल से चर्चा किए बिना ही हमले शुरू कर दिए। कथित उल्लंघन के बाद ईरान ने जोरदार जवाब दिया। बकौल रेजाई, 'समझौते के उल्लंघन के बाद 17 दिनों तक चले संघर्ष में हमने अमेरिका को करारा झटका दिया। हमने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास मिसाइलें और आत्मरक्षा की क्षमता दोनों हैं। अगर अमेरिका अनधिकृत मार्ग से होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्धपोत भेजता है।

एपस्टीन का द्वीप खरीदने वाला ताकझांक से परेशान

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के कुख्यात निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स और ग्रेट सेंट जेम्स अब एक नई वजह से चर्चा में हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, द्वीप खरीदने वाले अरबपति निवेशक स्टीफन डेकऑफ के लिए ये प्रॉपर्टी अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट बनाने वालों की वजह से बड़ी परेशानी बन गई है। डेकऑफ ने 2023 में दोनों द्वीप लगभग 6 करोड़ डॉलर (571 करोड़ रुपये) में खरीदे थे। उनको यहां एक लग्जरी रिसॉर्ट बनाना था, लेकिन चार साल बाद भी ऐसा न हो सका। इस बीच कई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर व कंटेंट क्रिएटर बिना अनुमति द्वीप पर पहुंचकर वीडियो बना रहे व ताकझांक कर रहे हैं। उनका दावा है कि वे एपस्टीन से जुड़े रहस्यों की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। 2019 में उसकी जेल में मौत हो गई थी, लेकिन उससे जुड़ी जानकारियों को लेकर आज भी लोगों में काफी दिलचस्पी है।

ट्रंप की नई टैरिफ नीति के खिलाफ 25 राज्य

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर चर्चा में है। 25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का आरोप है कि ये नए टैरिफ फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आयात करों को बदलने का बहाना हैं। पिछले महीने यानी जुलाई में अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंक वाले टैरिफ लगाए थे। ये टैरिफ जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर पर्याप्त कार्रवाई न करने के आरोप में लगाए गए। नए टैरिफ तब प्रभावी हुए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अस्थायी टैरिफ की समय सीमा समाप्त हो गई। सोमवार को (अमेरिकी समय) 25 राज्यों की तरफ से किए गए मकदमे के संबंध में न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा कि प्रशासन अवैध रूप से परिवारों और व्यवसायों पर कर बढ़ा रहा है। ट्रंप का तर्क है कि उच्च टैरिफ अमेरिकी विनिर्माण को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का हवाला दिया था। उन्होंने व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ लगाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि टैरिफ को अधिकृत नहीं करता। इस फैसले के बाद प्रशासन को टैरिफ का भुगतान करने वाले आयातकों को वापसी भेजनी पड़ी। राजस्व की भरपाई के लिए ट्रंप ने अस्थायी 10 फीसदी वैश्विक टैरिफ लगाए, जो 24 जुलाई को समाप्त हो गए। अब ट्रंप 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत अधिक स्थायी टैरिफ लगा रहे हैं। यह धारा राष्ट्रपति को अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल देशों के खिलाफ आयात कर लगाने की अनुमति देती है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का इस्तेमाल किया था,।

आतंक के आकाओं में भरा हत्या का खौफ

30 से ज्यादा आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने किया ढेर, लश्कर कमांडर ने खुद कबूला

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े एक वरिष्ठ आतंकी ने दावा किया है कि पिछले तीन से चार वर्षों में 30 से ज्यादा लश्कर आतंकियों की धुरंधर स्टाइल में हत्या की गई। लश्कर के आतंकी रिजवान हनीफ ने इन हत्याओं के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ होने का फर्जी दावा किया। उसने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत सरकार पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज कर चुकी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख और वरिष्ठ कमांडर रिजवान हनीफ यह दावा करता दिख रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 'अज्ञात हमलावरों' की मदद से लश्कर के कई आतंकियों की हत्या कराई।

हनीफ के मुताबिक, ये घटनाएं कराची, पेशावर, रावलपिंडी और पीओके के मुजफ्फराबाद तथा रावलाकोट में हुईं। आतंकी भर्ती और सीमा पार घुसपैठ में भूमिका के लिए कुख्यात रिजवान हनीफ वीडियो में हनीफ हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक और घृणा फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता भी सुनाई देता है।

पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे गए प्रमुख लश्कर आतंकियों में अबू सैफुल्लाह उर्फ रजाउल्लाह निजामानी का नाम भी शामिल है। वह वर्ष 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय पर हुए हमले का आरोपी था। उसकी सिंध में अज्ञात हमलावरों ने गोली

मारकर हत्या कर दी थी।

यह दावा ऐसे समय सामने आया है, जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। हनीफ ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। भारत सरकार पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज करती रही है। हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि कुलगाम में दो गैर-स्थानीय मजदूरों और अनंतनाग में दो पुलिसकर्मियों की हत्या की साजिश लश्कर कमांडर लतीफ भट और उसके सहयोगी वारिस शाह ने रची थी। जुलाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को आरोपी बनाया था। लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना 1980 के दशक के आखिर में पाकिस्तान में हाफिज मोहम्मद सईद, जफर इकबाल और अब्दुल्ला अज्जाम ने की थी।

मेक इन इंडिया से वैश्विक बाज़ारों तक नए एफडीआई नियम से 1.8 करोड़ एमएसएमई होंगे सशक्त, विकसित भारत के तहत 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को मिलेगी गति

एम्पावर इंडिया ने अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया उत्पादों के इन्वेंट्री-आधारित ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम बनाने वाले ऐतिहासिक प्रत्यक्ष एफडीआई नियम सुधार का स्वागत किया है। विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार, यह नीति भारत के 1.8 करोड़ विनिर्माण एमएसएमई के लिए परिवर्तनकारी अवसरों का द्वार खोलती है। इस अवसर पर एम्पावर इंडिया के महानिदेशक श्री के. गिरी ने कहा: यह नीति एक स्पष्ट और सशक्त संदेश देती है कि भारत बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए तैयार है। मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन करने की इच्छुक वैश्विक कंपनियों को अब एफडीआई समर्थित ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस के माध्यम से सीधे वैश्विक बाज़ारों तक पहुंच का मार्ग मिलेगा। केवल निर्यात के उद्देश्य से इन्वेंट्री-आधारित ई-कॉमर्स में एफडीआई की अनुमति देकर सरकार ने यह स्वीकार किया है कि वस्त्र, हस्तशिल्प, मसालों और अन्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाने वाले भारत के 1.8 करोड़ एमएसएमई क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि आवश्यक अवसंरचना के अभाव के कारण बड़े पैमाने पर निर्यात नहीं कर पा रहे थे। यह सुधार उसी बाधा को समाप्त करता है। नई व्यवस्था उन प्रमुख बाधाओं को दूर करती है जो अब तक छोटे निर्माताओं को वैश्विक निर्यात से जोड़ने में अवरोध बन रही थीं। यह ढांचा विशेषीकृत मध्यस्थों को सीमा-पार लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंच जैसी सेवाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है—ऐसी क्षमताएँ जो अब तक अधिकांश छोटे निर्माताओं की पहुंच से बाहर थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान जैसे प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में, जहाँ एमएसएमई वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, आभूषण, हस्तशिल्प और सुगंधित उत्पाद जैसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाते हैं, इस नीति से विशेष लाभ मिलेगा।

बंधन कॉन्ट्रा फंड का लक्ष्य बाज़ार की धारणा से परे अवसरों का लाभ उठाना

रायपुर: बंधन म्यूचुअल फंड ने आज बंधन कॉन्ट्रा फंड के लॉन्च की घोषणा की। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना है, जो विपरीत (कॉन्ट्रेरियन) निवेश रणनीति का अनुसरण करती है। इस फंड का उद्देश्य ऐसे मूलभूत रूप से मजबूत व्यवसायों की पहचान करना है, जो सेक्टर-स्तरीय चिंताओं, चक्रीय चुनौतियों, व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं या मौजूदा बाज़ार धारणा के कारण अस्थायी रूप से निवेशकों की पसंद से बाहर हों, लेकिन समय के साथ धारणा और मूलभूत कारकों में सुधार होने पर जिनके पुनर्मूल्यांकन (री-रेटिंग) की संभावना हो। न्यू फंड ऑफर (हस्नह्र) सोमवार, 10 अगस्त को खुलेगा और सोमवार, 24 अगस्त को बंद होगा। बंधन कॉन्ट्रा फंड में निवेश लाइसेंस प्राप्त म्यूचुअल फंड वितरकों, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तथा सीधे https://bandhanmutual.com/nfo/bandhan-contra-fund/ के माध्यम से किया जा सकता है। बन्धन कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात करते हुए, बंधन एएमसी के सीईओ विशाल कपूर ने कहा, बंधन कॉन्ट्रा फंड ऐसे समय में लॉन्च किया गया है जब विभिन्न सेक्टरों के वैल्यूएशन में अंतर काफी बढ़ गया है, जिससे चुनिंदा कॉन्ट्रेरियन निवेश के अवसर पैदा हुए हैं। कई सेक्टर और कंपनियाँ मजबूत कारोबारी मॉडल, आय में सुधार की बेहतर संभावनाओं और सुदृढ़ बैलेंस शीट के बावजूद अभी भी अपनी दीर्घकालिक क्षमता से कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रही हैं। यह सेक्टोरल अंतर उन निवेशकों के लिए अवसर प्रदान कर सकता है जो प्रचलित बाज़ार धारणा से आगे बढ़कर निवेश करना चाहते हैं। बंधन कॉन्ट्रा फंड एक अनुशासित कॉन्ट्रेरियन ढाँचे के तहत ग्रोथ-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाते हुए बेहतर होते मूलभूत कारकों, आय में सुधार और भविष्य में संभावित री-रेटिंग का लाभ उठाने का प्रयास करेगा। बंधन कॉन्ट्रा फंड उन निवेशकों के लिए तैयार किया गया है जो एक अलग प्रकार की इक्विटी रणनीति चाहते हैं, जो पारंपरिक ग्रोथ और वैल्यू निवेश आवंटन का पूरक बन सके। यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनका निवेश क्षितिज दीर्घकालिक है और जो बाज़ार के विभिन्न चक्रों के दौरान निवेशित रह सकते हैं।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने इंडिया एसएमई फोरम के अब तक के सबसे बड़े एमएसएमई डिजिटल प्रोक्योरमेंट सर्वे का किया अनावरण

नई दिल्ली: इंडिया एसएमई फोरम (आईएसएफ) ने आज डिजिटल भारत: इंडिया डिजिटल प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की। यह एमएसएमई के खरीद व्यवहार (प्रोक्योरमेंट) और डिजिटल अपनाने की प्रवृत्ति पर भारत के सबसे व्यापक अध्ययनों में से एक है। देश के 515.3 लाख उद्यम-पंजीकृत एमएसएमई को शामिल करने वाली इस रिपोर्ट का विमोचन केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री एवं श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किया। इस अवसर पर एमएसएमई उद्योग के प्रमुख, उद्यमी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें डीपीआईआईटी के अपर सचिव श्री अतीश कुमार सिंह और एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव ी केशवेंद्र कुमार (आईएएस) शामिल हैं। इंडिया एसएमई फोरम (आईएसएफ) की यह रिपोर्ट आधिकारिक उद्यम पंजीकरण के आंकड़ों पर आधारित स्वामित्व वाले एमएसएमई प्रोक्योरमेंट इकोनॉमी मॉडल (एमपीईएम) के जरिए तैयार की गई है। यह रिपोर्ट भारत की एमएसएमई प्रोक्योरमेंट अर्थव्यवस्था का पहला व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है और इस क्षेत्र में डिजिटल अपनाने की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों के उद्यमों को शामिल करने वाले भारत के सबसे बड़े एमएसएमई प्रोक्योरमेंट सर्वेक्षणों में से एक पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की एमएसएमई प्रोक्योरमेंट अर्थव्यवस्था का आकार 124.9 लाख करोड़ रुपये (124.9 ट्रिलियन रूपये) आंका गया है, जो देश की सबसे बड़ी व्यावसायिक व्यय श्रेणियों में से एक है।

चौथे दिन जारी झड़प में कई घायल

अफगानिस्तान में कबीलों के बीच जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप

काबुल, एजेंसी। दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान में खोस्त और पक्तिया प्रांतों की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी इलाके के मालिकाना हक को लेकर दो कबीलों के बीच हुई सशस्त्र झड़पें सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहीं। अफगानिस्तान की प्रमुख समाचार एजेंसी खामा प्रेस के मुताबिक, यह झड़प खोस्त प्रांत के स्पाइरा जिले के बोरी खेल कबीले और पक्तिका प्रांत के गियान जिले के गियान खेल कबीले के लोगों के बीच शुरू हुई।

स्थानीय रिपोर्टों का हवाला देते हुए एजेंसी ने बताया कि दोनों पक्षों ने संघर्ष के दौरान हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इससे लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद के और बढ़ने की चिंता पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, विवादित पहाड़ स्पाइरा और गियान जिलों के बीच स्थित है। यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, जिनमें कीमती पाइन नट के पेड़ भी हैं। लोगों का कहना है कि इन्हीं संसाधनों की वजह से जमीन के मालिकाना हक, उपयोग और नियंत्रण को लेकर मतभेद और बढ़ गए हैं। कई दशकों से यह विवाद समय-समय पर सशस्त्र झड़पों का कारण बनता रहा है। स्पाइरा जिले के निवासी शाह मीर खान ने कहा कि पहले भी इस पहाड़ को लेकर हुई झड़पों में भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। उनका दावा है कि इस विवाद से जुड़े पुराने संघर्षों में करीब 80 लोग मारे गए या घायल हुए थे। हालांकि, इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। रेडियो हुर्रियत के अनुसार, हालात को और बिगड़ने से रोकने और दोनों पक्षों को अलग करने के लिए तालिबान बलों को इलाके में तैनात किया गया है।

चीन में हर विदेशी पर रहती है खुफिया नजर

डाटा लीक ने खोली पोल, हर गतिविधि की बनती है डिजिटल प्रोफाइल

न्यूयॉर्क, एजेंसी। कोई विदेशी नागरिक, पर्यटक या व्यवसायी जैसे ही चीन की धरती पर कदम रखता है, उसकी हर छोटी-बड़ी हरकत पर खुफिया नजरें टिक जाती हैं। वीजा रिकार्ड से लेकर उसके होटल में ठहरने, कहीं आने-जाने, खाने-पीने तक की रीयल टाइम मॉनीटरिंग होती है और बाकायदा डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर लिया जाता है।

चीनी प्रशासन अपनी व्यापक निगरानी प्रणालियों को आतंकवाद और अपराध रोकने का जरिया बताता है, लेकिन इसे सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत गोपनीयता का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। यह सब चीनी पुलिस और निगरानी तकनीकी कंपनियों के संगठित तंत्र के तहत चल रहा है। कंपनियां पुलिस की जरूरतों के मुताबिक रोबोटिक्स, फेशियल रिकग्निशन और डायनेमिक कंट्रोल प्लेटफॉर्म जैसे उन्नत सर्विलांस सिस्टम तैयार करती हैं।

डाटा सुरक्षा के लिए नहीं किए जाते कोई इंतजाम

ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया उप-निदेशक माया वांग का कहना है, अन्य देश भी निगरानी प्रणालियों का उपयोग करते हैं, लेकिन चीन में पुलिस की मनमानी के खिलाफ बहुत कम सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। कनाडा की एक शोध फर्म सेकदेव ग्रुप से जुड़े वाल्टन ने कहा कि प्रत्येक नया प्लेटफॉर्म उन स्थानों की संख्या को बढ़ाता है जहां संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा को गलत तरीके से कॉपी किया जा सकता है या बाहरी रूप से खोजा जा सकता है।

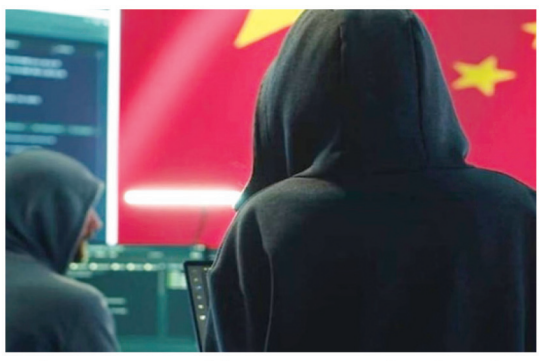

ऐसे खुला राज: चीन में खुफिया निगरानी का खुलासा असुरक्षित पुलिस डैशबोर्ड का डाटा लीक होने से हुआ। दरअसल, एम्सटर्डम के एक साइबर सुरक्षा शोधकर्ता और पत्रकार मार्क होफर एक दिन इंटरनेट पर कुछ खंगाल रहे थे, जब उनकी नजर ओवरसीज पर्सनल के लिए डायनेमिक कंट्रोल प्लेटफॉर्म पर पड़ी। उन्होंने इसे थोड़ा खंगाला तो पाया कि इसकी मदद से चीनी शहर झांगजियाको में विदेशियों पर नजर रखी जा रही थी।

झांगजियाको एक लोकप्रिय स्कीइंग स्थल है जिसने 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की सह-मेजबानी की थी। डैशबोर्ड के अनुसार, इसमें शहर में रहने वाले 700 से अधिक विदेशी नागरिकों पर नजर रखी जा रही थी।

विकसित भारत जी रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बेरला में सरपंचों का प्रशिक्षण संपन्न

बेमेतरा/मूक पत्रिका

विकसित भारत जी रामजी (ङ्क्वत्तन्नस्त्र) योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनपद पंचायत बेरला में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जनपद पंचायत बेरला अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए योजना के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पंचायत बेमेतरा से आए सहायक परियोजना अधिकारी श्री नवीन साहू ने विकसित भारत जी रामजी योजना की अवधारणा, ग्राम विकास की समग्र कार्ययोजना, योजनाओं के प्रभावी अभिसरण, जनभागीदारी, संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा पंचायतों की भूमिका पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं विकासोन्मुख बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ विकास सुनिश्चित करना है। इस दौरान उन्होंने सरपंचों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए योजना के सफल संचालन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं की भी जानकारी दी।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत बेरला की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री दिव्या ठाकुर ने सभी सरपंचों से आह्वान किया कि वे योजना के प्रत्येक प्रावधान का गंभीरता से अध्ययन कर ग्राम पंचायत स्तर पर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता तथा जनसहयोग से ही ग्रामीण विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने पंचायतों में गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों के चयन, विभिन्न विभागों की योजनाओं के समन्वय, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा विकास कार्यों की सतत निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की क्षमता का विकास कर उन्हें ग्राम स्तर पर योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए सक्षम बनाना था, ताकि विकसित भारत के संकल्प को ग्राम स्तर पर सफलतापूर्वक साकार किया जा सके। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कश्यप, एस.डी.ओ. (आर.ई.एस.) श्री आसित गोलछा, जनपद पंचायत बेरला के अधिकारी-कर्मचारी तथा सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित रहे।

दिव्यांग बच्चों के लिए प्रमाण पत्र शिविर आयोजित, 37 बच्चों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण एवं प्रमाणीकरण

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में दिव्यांग बच्चों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय बेमेतरा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेडर के मार्गदर्शन तथा सिविल सर्जन डॉ. लोकेश साहू एवं जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से आयोजित इस शिविर में विकासखंड बेमेतरा के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष सहायता प्राप्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।शिविर में चिन्हित बच्चों को जिला चिकित्सालय लाकर हड्डी रोग विशेषज्ञ, नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, एम.डी. मेडिसिन एवं सर्जन सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण की गुणवत्ता का निरीक्षण भी किया।शिविर में कुल 37 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में जिले के सभी विकासखंडों में भी इसी प्रकार के शिविर आयोजित कर पात्र बच्चों का परीक्षण किया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। शिविर के दौरान डॉ. बी.एल. राज (नोडल अधिकारी), सिविल सर्जन, अस्पताल सलाहकार, आरबीएसके (ऋक्ष्य) टीम तथा सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

गुरूघासीदास वार्ड में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का किया गया शिलान्यास

अंबिकापुर। शहर के आंगनबाड़ी भवन विहीन वार्ड गुरुघासीदास वार्ड में पार्षद शुभम जायसवाल के प्रयास से गुरुवार को पहला आंगनबाड़ी भवन मिला है। इस वार्ड में कुल 3 आंगनबाड़ी मौजूद हैं जो किराये के भवन में संचालित हैं।

आज इस क्षेत्र के पहले आंगनबाड़ी भवन का शिलान्यास जिसका निर्माण 12 लाख रुपए की लागत से होना है। प्रस्तावित आंगनबाड़ी का शिलान्यास आखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी एवं एमआईसी सदस्य मनीष सिंह की मौजूदगी में हुआ। इसके साथ ही 3 लाख 20 हजार की लागत से इस वार्ड की जर्जर पड़ी नालियों के मरम्मत कार्य का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अमित सिन्हा, पूर्व पार्षद शेखर झरिया, उमा देवी राजवाड़े, श्रीकांत सिन्हा, मिथुन सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, सूरज तिवारी, मुकेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, कबीर गोस्वामी, आशुतोष मिश्रा, सुरेश सोनी, सुरेंद्र सोनी, लाल विजय, समीर सक्षम, साहिल, महेंद्र सूर्यवंशी, वनस झा, आर्यन सहित बड़ी संख्या में गुरु घासीदास वार्ड के निवासी मौजूद थे।

शासकीय डेयरी पॉलीटेक्नीक के विद्यार्थियों को मिल्क प्रोडक्टस बनाने की विधि का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया

बेमेतरा/मूक पत्रिका

चोरभट्ठी स्थित शासकीय डेयरी पॉलीटेक्निक, बेमेतरा में विद्यार्थियों को डेयरी उत्पाद निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. चन्द्रहास साहू तथा असिस्टेंट टीचर्स कु. अनुभूति द्विवेदी, कु. प्रीति खुंटे एवं कु. निकिता शर्मा के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला में कुल्हड़ रबड़ी, व्हे ड्रिंक और पनीर निर्माण की विधि का प्रायोगिक अभ्यास किया। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान तैयार किए गए उत्पादों को समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया जाता है। इससे विद्यार्थियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, साथ ही डेयरी उत्पादों के विपणन और उद्यमिता का व्यावहारिक अनुभव भी मिलता है। वहीं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध, मिलावट रहित एवं गुणवत्तापूर्ण डेयरी उत्पाद उपलब्ध होते हैं। महाविद्यालय द्वारा भविष्य में फ्लेवर्ड मिल्क, खोआ, रसगुल्ला, मीठा दही सहित अन्य डेयरी उत्पादों का निर्माण कर उन्हें बेमेतरा शहर के उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन एवं दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनू विश्वविद्यालय के सहयोग से ग्राम चोरभट्ठी में संचालित शासकीय डेयरी पॉलीटेक्निक में कक्षा 12वीं गणित अथवा जीवविज्ञान विषय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जो 12वीं के बाद तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त करना चाहते हैं।महाविद्यालय का दो वर्षीय (चार सेमेस्टर) पाठ्यक्रम तेजी से विकसित हो रहे डेयरी उद्योग के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर केंद्रित है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी डेयरी संस्थानों में रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के भी व्यापक अवसर उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। गणित एवं जीवविज्ञान विषय से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए डेयरी सेक्टर में करियर बनाने का यह सुनहरा अवसर है। प्रवेश एवं अन्य जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी शासकीय डेयरी पॉलीटेक्निक, चोरभट्ठी से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9200172864, 8964844803, 9340291259, 7000231858, 7000240762 एवं 9098360150 पर संपर्क किया जा सकता है।

बीजापुर-सुकमा सीमा पर क्रेशर प्लांट को लेकर कांग्रेस का विरोध

तुमलपाड़ पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी व हरीश कवासी, ग्रामीणों ने बिना ग्रामसभा अनुमति संचालन का लगाया आरोप

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। बिते गुरुदेव को बीजापुर-सुकमा सीमा से लगे ग्राम तुमलपाड़ में संचालित गिट्टी क्रेशर प्लांट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। विधायक विक्रम मंडावी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने मौके पर पहुंचकर प्लांट का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्रामसभा की सहमति और आवश्यक स्वीकृतियों के बिना प्लांट संचालित किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि प्लांट स्थापित करने से पहले ग्रामसभा की बैठक नहीं हुई और पंचायत की सहमति भी नहीं ली गई। उनका आरोप है कि प्लांट में लगातार ब्लास्टिंग होने से कंपन महसूस होता है, धूल उड़ती है और आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से प्लांट बंद कराने की मांग की।निरीक्षण के दौरान विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि यदि प्लांट के संचालन के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति नहीं है तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि आदिवासी क्षेत्र में ग्रामसभा, वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों की अनुमति के बिना इस तरह का संचालन कैसे हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सुकमा जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि नियमों के विपरीत प्लांट संचालित हो रहा है तो उसे तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा कांग्रेस आंदोलन करेगी। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

- ग्रामसभा की सहमति के बिना प्लांट संचालन का आरोप।
- वन एवं अन्य विभागों की अनुमति पर उठाए सवाल।
- अवैध संचालन की जांच कर कार्रवाई की मांग।- कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी।यदि सभी आवश्यक अनुमतियां नहीं हैं तो यह प्लांट किसकी अनुमति और संरक्षण में संचालित हो रहा है? प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे - विधायक विक्रम मंडावीबस्तर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्लांट नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहा है तो उसे तत्काल बंद किया जाए - हरीश कवासी

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में तहसीलदारों का तबादला, कोमल साहू को बरमकेला और पुष्पेंद्र राज को सरिया का प्रभार, कलेक्टर ने जारी किया आदेश..

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने चार राजस्व अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण और कार्यालयीन कार्यों के सुचारू संचालन को देखते हुए अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं।

इन अधिकारियों का हुआ तबादला

* कमलेश कुमार सिदार को तहसीलदार बिलाईगढ़ से तहसीलदार भटगांव बनाया गया है।
* निलिमा अग्रवाल को तहसीलदार भटगांव से तहसीलदार बिलाईगढ़ पदस्थ किया गया है।
* पुष्पेंद्र कुमार राज को तहसीलदार बरमकेला से तहसीलदार सरिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
* कोमल प्रसाद साहू, जो वर्तमान में प्रभारी तहसीलदार सरिया थे, उन्हें प्रभारी तहसीलदार बरमकेला बनाया गया है।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश-कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर का कहना है कि इस फेरबदल से राजस्व कार्यों के संचालन में और अधिक गति आएगी तथा आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

राज्य के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित, मिलेगी सरकारी नौकरी, सारंगढ़ जिले के 4 खिलाड़ियों के नाम शामिल..

10 साल का इंतजार खत्म

छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

करीब एक दशक से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दिए हैं। राजपत्र में 156 खिलाड़ियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिससे अब इन खिलाड़ियों की शासकीय सेवा में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।ये सभी खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ और देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद लंबे समय से उन्हें सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजपत्र में नाम प्रकाशित होने के बाद खिलाड़ियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। अब उम्मीद की जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी।

खेल जगत ने फैसले का किया स्वागत

खेल से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश के युवा खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे। लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया के पूरी होने को खिलाड़ियों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के चार खिलाड़ियों को भी मिला सम्मान

राज्य की इस सूची में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के चार खिलाड़ियों ने भी जगह बनाई है। सॉफ्टबॉल के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता वसीम मोहम्मद, सौरभ यादव, सूरज अग्रवाल और रितेश यादव का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना के तहत शासकीय सेवा के लिए किया गया है। चारों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब राजपत्र में नाम प्रकाशित होने के बाद उनके सरकारी नौकरी पाने का रास्ता भी साफ हो गया है। इस उपलब्धि पर जिला खेल संघ सहित जिले के खेल प्रेमियों ने चारों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता

उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने के बावजूद वर्षों तक नियुक्ति नहीं मिलने से खिलाड़ी निराश थे। अब सरकार के इस फैसले से न केवल 156 खिलाड़ियों को राहत मिली है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों का सम्मान किया जाएगा। इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।